20 सितम्बर, 2022 * वर्ष 31, पृष्ठ संख्या 60, अंक-9

राजस्थान सुजस

सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक

काष्ठ कला

चित्तौड़गढ़ जिले के बसी गांव की काष्ठकला प्रसिद्ध है। यहां वर्षों से काष्ठनिर्मित विविध-रूपा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का जो प्रयत्न किया गया है, वह स्तुत्य है। काष्ठ-कलारूपों में कठपुतली, चोपड़े, माणकथम्भ, तोरण, बाजोट, वेवाण, मुखौटे, खाण्डे, झूले-हिंडोले आदि के साथ सर्वाधिक चर्चित कावड़ है। नये प्रयोग करते हुए विविध महापुरुषों, राष्ट्रनायकों तथा लोकदेवताओं पर सौ से अधिक काष्ठ कलाएं बनाई गई हैं। सबसे छोटी माचिस के आकार की कावड़ से लेकर सबसे बड़ी 8 फीट ऊंची, 20 फीट लम्बी तथा साढ़े तीन क्विंटल वजनी कावड़ बनाई, जो उदयपुर के पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के संग्रहालय में दर्शकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है।

आलेख एवं छाया : डॉ. महेन्द्र भानावत

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

•

सम्पादक
अलका सक्सेना

•

सह-सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

•

उप-सम्पादक
सम्पत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

•

आवरण छाया
सूजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. नं. 98292-71189
94136-24352
e-mail :
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 31 अंक : 09 | सितम्बर, 2022

इस अंक में

लोक जीवन	02
सम्पादकीय	04
साकार होंगे आत्मनिर्भरता से...	20
राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलोजी	22
अभय कमांड सेंटर	25
राजस्थान की गौरवमयी गाथा	32
गौरवशाली विरासत हैः गागरोन का जलदुर्ग	45
स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा...	46
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना	48
पर्यावरण	49
प्रकाश एक अभियान	50
महिला सशक्तीकरण	51
कॉकलियर इम्प्लांट	53
आवाज ही जिनकी पहचान थी	58
धरोहर	59
तस्वीर बदलाव की	60

सूचना प्रौद्योगिकी में...

05

बातचीत

18

सामयिकी

35

फोटो फीचर

30-31

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

साक्षात्कार

14

फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी

26

खेल खिलाड़ी

54

ई-गवर्नेंस में अव्वल राजस्थान

संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन का अभिन्न अंग है सूचना प्रौद्योगिकी। ई-गवर्नेंस के बिना आमजन को बेहतर और त्वरित सर्विस डिलीवरी की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यह प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी पायदान पर है।

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग से शासन-प्रशासन की कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आया है। राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ अंतिम छोर तक सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है। कोविड काल के दौरान तो सूचना प्रौद्योगिकी का महत्त्व और अधिक रेखांकित हुआ। आज ग्राम पंचायत से लेकर राजधानी तक वर्चुअल माध्यम से ही बैठकों का आयोजन कर राजकीय कार्यों को अल्पसमय में सम्पादित किया जा रहा है।

जन आधार योजना ई-गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम है, जिसमें प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 93 लाख परिवार नामांकित हो चुके हैं। जन सूचना पोर्टल एवं जनकल्याण पोर्टल जैसे नवाचारों से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की आवश्यक जानकारी आमजन को आसानी से उपलब्ध हो रही है। आशा है यह सूचना क्रांति राजस्थान के विकास को नए आयाम प्रदान करेगी।

राजस्थान सुजस का सितम्बर माह का अंक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है। राज्य में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी इस अंक में शामिल किया गया है।

सादर अभिवादन एवं मंगलकामनाओं सहित,

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान सम्पादक

सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान के मजबूत कदम

सूचना प्रौद्योगिकी ने बहुत ही कम समय में देश-दुनिया की तस्वीर बदल दी है। सभी जगह सूचना तकनीक ने नागरिकों का कार्य आसान किया है। कुछ ही पल में एक-दूसरे तक वर्चुअली पहुंचना संभव हुआ है। शासन और प्रशासन में ई-गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, उनसे प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी सभी कार्यों को गति मिली है। सूचना तकनीक के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी द्वारा चलायी गई यह लहर आज मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक क्रांति का रूप ले चुकी है। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान कर कार्यों को आसान बनाया जा सके।

राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने प्रदेश की ज्यादातर नागरिक सेवाओं की त्वरित पहुंच सूचना तकनीक के माध्यम से सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पारदर्शी और जवाबदेही सुशासन की मंशा को विभाग कई परियोजनाओं के माध्यम से पूरा कर रहा है। यहां ऐसी ही कुछ चुनिंदा परियोजनाओं की जानकारी दी जा रही है।

जन आधार योजना : पारदर्शी तरीके से मिल रहा योजनाओं का लाभ

राज्य सरकार ई-गवर्नेंस को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर प्रदेशवासियों के लिए सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए

डॉ. आशीष खण्डेलवाल
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

प्रयासरत है। सरकार अपने संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सुशासन के उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में आम लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी लीकेज के तेजी से पहुंचा रही है। जन आधार योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें प्रदेश के लगभग 1.93 करोड़ परिवार नामांकित हो चुके हैं। इन परिवारों के करीब 7.48 करोड़ नामांकित सदस्यों को सरकारी योजनाओं के लाभ उनकी पात्रतानुसार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू हुई जन आधार योजना आमजन तक योजनाओं के लाभ सरलता एवं सुगमता से पहुंचाने में कारगर सिद्ध हो रही है।

- अब तक लाभार्थियों के बैंक खातों में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरण किए जा चुके हैं।
- नकद और गैर नकद लाभ के 119 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन किए गए हैं।
- योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है।
- भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में इस योजना की भूमिका कारगर सिद्ध हो रही है।
- राज्य सरकार की 70 योजनाएं जन आधार से जुड़ी हैं।
- योजना की एक विशेषता यह है कि जन आधार कार्ड में परिवार की मुखिया महिला को चुना जाता है। इससे समाज में महिला सशक्तीकरण को बल मिला है।
- जन आधार कार्ड के माध्यम से सरकार की योजनाओं के लाभ के साथ ही इसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है।
- इस महत्त्वाकांक्षी योजना में प्रत्येक परिवार का जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।

जन सूचना पोर्टल: सूचना के अधिकार का उद्देश्य साकार

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की भावना और जन अधिकार कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप काम करते हुए संवेदनशील, जवाबदेही और पारदर्शी शासन के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की पालना में स्थापित जन सूचना पोर्टल इसी संकल्प को साकार कर रहा है। इस पोर्टल पर अभी तक 115 विभागों की 326 योजनाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं और आमजन इस पर 684 तरह की जानकारियां हासिल कर रहे हैं।

सफलता के आंकड़े

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सूचना के अधिकार के प्रारंभ से ही समर्थक रहे हैं। उनकी मंशा है कि आम आदमी को सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल की परिकल्पना को साकार करते हुए 13 सितंबर, 2019 को पोर्टल प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया। विजिटर्स के आंकड़े इस पोर्टल की सफलता की पुष्टि करते हैं। लगभग

तीन वर्ष के कम समय में इस पोर्टल को 11.47 करोड़ से अधिक लोगों ने विजिट किया है और इस पर 15.05 करोड़ से अधिक सूचनाएं अभी तक एक्सेस की जा चुकी हैं।

क्या है जन सूचना पोर्टल https://jansoochna.rajasthan.gov.in

राजस्थान देश में पहला राज्य है, जिसने आपकी सूचना, आपका हक की परिभाषा को अपनाते हुए सूचना को जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सभी तरह की सूचनाएं आमजन तक पहुंचाई है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आमजन को सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (2) की मूल भावना से प्रेरित है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़ी सूचनाएं सरल भाषा में एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। इससे जहां आम आदमी को राहत मिल रही है, वही सरकारी कामकाज में गति आ रही है, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार से निजात मिल रही है, सरकारी विभागों से आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारियों की अर्जियों में कमी आ रही है और आम आदमी को सम्बन्धित जानकारी घर बैठे सुलभ हो पा रही है।

जन कल्याण पोर्टल

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर, 2020 को राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें दीं। उनके द्वारा प्रदेश में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जन कल्याण पोर्टल (पब्लिक वेलफेयर पोर्टल) लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और दस्तावेजों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आमजन इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की हमेशा यह मंशा रही है कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ हर गरीब व जरूरतमंदों तक पहुंचे। प्रशासन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए उनकी पहल पर जन सूचना पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से आमजन किसी भी योजना के बारे में, योजना की शर्तें, पात्रता आवेदन कैसे करें या किस वेबसाइट के

माध्यम से करें आदि की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके माध्यम से किसान, छात्र, अल्पसंख्यक, महिला, व्यवसायी आदि अपने लिए उपयोगी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस पोर्टल पर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की भी जानकारी उपलब्ध है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए जनकल्याणकारी मोबाइल ऐप्स की जानकारी भी उपलब्ध है, जिनके उपयोग से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। jankalyan.rajasthan.gov.in पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सुशासन को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि आमजन तक राज्य सरकार की योजनाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो।

राज किसान साथी पोर्टल

इस पोर्टल की शुरुआत किसानों को विभिन्न सुविधाएं एवं सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए की गई। साथ ही यहाँ किसानों से जुड़े विभिन्न अनुदान से सम्बन्धित आवेदन भी ऑनलाइन किये जा सकते हैं। कृषकों को देय अनुदान का लेखा-जोखा रखने एवं सभी योजनाओं की पारदर्शिता के लिए इस पोर्टल का संचालन कृषक हित में किया जा रहा है। पोर्टल पर सिर्फ कृषि विभाग ही नहीं बल्कि उद्यानिकी विभाग, कृषि विपणन, पशुपालन विभाग एवं अन्य के बारे में विस्तृत जानकारी एवं सेवाएं उपलब्ध हैं जिनका कृषक आसानी से ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं।

ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए कृषकों को जन आधार से भी जोड़ा जा रहा है ताकि सभी को एक साथ जन आधार से जुड़े खातों पर भुगतान का वितरण एवं सम्बन्धित मोबाइल नंबर के माध्यम से अन्य जानकारी व सेवाएं प्रदान की जा सके। किसान के सामने आने वाली बीज-खाद, सिंचाई, भुगतान सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को इस पोर्टल के माध्यम से लगभग ख़त्म कर दिया गया है।

कृषक राज्य का अभिन्न हिस्सा हैं एवं इनकी देखभाल राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं जन उपयोगी सेवाओं के माध्यम से बखूबी कर रही है। किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की तर्ज पर विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि कृषि कार्यों का सरलीकरण हो सके एवं किसानों को उनकी मेहनत का पूरा एवं समयबद्ध लाभ मिल सके। कृषि क्षेत्र के विकास और कृषक कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गए कार्य वाकई सराहनीय हैं।

राजनिवेश पोर्टल: आसान हो रही निवेशकों की राह

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए सुधारों का परिणाम है कि प्रदेश में इन्वेस्ट राजस्थान समिट, 2022 के तहत पिछले कुछ महीनों में विभिन्न शहरों में निवेश कार्यक्रम आयोजित कर बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव किए जा चुके हैं। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है और रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को सुगम बनाने के लिए रिप्स, 2019 लागू की गई है। प्रदेश में निवेश के

लिए स्वीकृतियां प्राप्त करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशकों को बाधा रहित स्वीकृति समय पर प्रदान की जा रही है।

वन स्टॉप शॉप के तहत एक ही छत के नीचे समयबद्ध तरीके से प्रस्तावों के अनुमोदन, मंजूरी, अनुमति में तेजी लाई जा रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड का गठन किया गया है जो मंत्रिपरिषद् के स्थान पर निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर रहा है। इसमें 14 विभागों के अधिकारियों को 136 प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है।

इस सुविधा को और प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए राजनिवेश पोर्टल शुरू किया गया है। rajnivesh.rajasthan.gov.in पोर्टल पर निवेशक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और स्वीकृतियां प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के प्रति जागरूकता लाने के लिए निवेशकों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की गई।

इस पोर्टल पर अब तक 61,818 करोड़ रुपये के 226 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार प्रदेश में निवेशकों को निवेश में असुविधा नहीं हो, इसके लिए वन स्टॉप शॉप की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। इससे प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिला है और प्रदेश निवेश के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन कर उभर रहा है।

राज उद्योग मित्र पोर्टल

यदि कोई व्यक्ति नये सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों को शुरू करना या उसे संचालित करना चाहता है, तो उसे एमएसएमई एक्ट 2019 के तहत राज्य में तीन साल तक किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी राज उद्योग मित्र पोर्टल पर आधार नंबर के माध्यम से रजिस्टर करके 3 साल तक का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकता है। तीन साल की अवधि के लिए किसी भी कानून के तहत उसके उद्यम का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। इस योजना में मुख्य रूप से उन व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन करने का लाभ प्राप्त होगा, जो नये व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। इस एक्ट का उद्देश्य राज्य में आजीविका, समावेशी आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। पोर्टल का लिंक https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in है जिसके माध्यम से अब तक कुल 14,834 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

राजस्थान सम्पर्क

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल आमजन को विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने एवं समाधान प्रक्रिया की ट्रैकिंग के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है। साथ ही, विभागीय अधिकारियों को आमजन द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान हेतु माध्यम प्रदान करता है। परियोजना के उद्देश्यों में शिकायत निवारण के विभिन्न तरीकों से नागरिकों की शिकायत निवारण के लिए केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म की

स्थापना शामिल है। साथ ही शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए रिपोर्ट के माध्यम से शिकायतों की उचित ट्रैकिंग व सक्षम निगरानी करना और सभी विभागों के लिए शिकायत निवारण की समरूप और प्रमाणीकृत प्रक्रिया बनाना भी इसका उद्देश्य है। प्रतिदिन लगभग 50,000 से अधिक कॉल इस सम्बन्ध में आ रहे हैं।

ई-मित्र

राज्य मे 85 हजार से अधिक ई-मित्र कियोस्कों (लगभग 60 हजार से अधिक ग्रामीण क्षेत्र मे एवं 25 हजार से अधिक शहरी क्षेत्र में) के माध्यम से आमजन को सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र की लगभग 475 नागरिकोन्मुखी सेवाएं प्रभावशाली एवं पारदर्शी प्रणाली से घर के नजदीक उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आमजन द्वारा ई-मित्र की सेवाएं ई-मित्र कियोस्क, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल एवं ई-मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से भी प्राप्त की जा रही हैं।

ई-मित्र प्लस

ई-मित्र प्लस, ई-सेवा प्रदान करने में एक क्रान्तिकारी कदम है। मानवरहित स्वयंसेवी ई-मित्र प्लस कियोस्कों को सरकारी कार्यालयों, संगठनों, सार्वजनिक स्थानों एवं साथ ही गैर सरकारी स्थानों पर स्थापित किया गया है। ई-मित्र प्लस भारत में अपनी तरह का पहला कियोस्क है। इन पर नकद, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की कई सुविधाएं हैं और बायोमेट्रिक के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं जैसे बिल आदि का भुगतान भी कर सकते हैं। इन स्वचालित कियोस्कों से विभिन्न प्रमाण पत्र, ई कार्ड (आधार, जन

आधार), पी.वी.सी. कार्ड पर जनआधार प्रिंट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, जन सुनवाई, सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं राजकीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में लगभग 15 हजार ई-मित्र प्लस कियोस्क ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्थापित हैं।

वीडियोवॉल

राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर तक के निवासियों के लिये विभिन्न सरकारी नवाचारों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और लाइव इवेन्ट्स की ऑडियो-वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रसारण करने के लिये वीडियोवॉल की स्थापना की गई है। इस वीडियोवॉल पर स्वचलित सूचनाएं समय-समय पर प्रसारित होती हैं तथा कार्यक्रमों का दृश्य-श्रव्य प्रसारण होता है।

राजवीसी

राजस्थान सरकार ने विभाग मुख्यालय, विभाग कार्यालयों, जिला मुख्यालयों, उपखण्ड, तहसील कार्यालयों, नगर निगमों और ब्लॉक मुख्यालयों में हार्डवेयर आधारित वीसी सेटअप स्थापित किया है। जोधपुर में एक डीआर साइट भी मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई है ताकि पूरे राजस्थान में नेटवर्क विफल होने की स्थिति में उपयोगकर्ता के लिए निर्बाध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रबंध किया जा सके। राजस्थान/राजनेट नेटवर्क का उपयोग पूरे राजस्थान में अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा की उपलब्धता के लिए किया जाता है। वीसी सुविधा के अलावा, राजस्थान सरकार ने राज्य में संभाग मुख्यालय स्तर पर एवं राज्य मुख्यालय जयपुर में दो और राजस्थान के बाकी संभाग मुख्यालयों उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में इमर्सिव टेलीप्रेजेंस स्टूडियो भी स्थापित किए गए हैं।

राजनेट

ग्रामीण राजस्थान के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राजनेट परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को राजनेट कनेक्टिविटी द्वारा जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से ई-मित्र, ई-मित्र प्लस, आईपी टेलीफोन, वाई-फाई, स्काडा, बैंकिंग कॉरेस्पोडेंट आदि को कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य इंटरनेट नेटवर्क का निर्माण करके राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना है। इस सुविधा का उपयोग ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर सेवाओं को ई-मित्र के माध्यम से ग्रामवासियों को उपलब्ध करवाने के लिये किया जा रहा है। विभिन्न नेटवर्कों के प्रभावी उपयोग के लिए केंद्रीय एकीकृत नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र के माध्यम से नेटवर्क की निगरानी की जा रही है और नेटवर्क सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग 9400 से ज्यादा ग्राम पंचायतें एमपीएलएस/वी-सेट तकनीकी के माध्यम से जोड़ी गयी हैं। भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत ओएफसी के माध्यम से 7100 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

राज वाईफाई

राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सुधारों के तहत ग्राम पंचायत एवं विभिन्न सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने की कल्पना की है। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से राज वाईफाई परियोजना संचालित की जा रही है। वाइफाइ की सुविधा सभी विभागीय मुख्यालयों एवं समस्त जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करा दी गई है। राज्य की कुल 11341 ग्राम पंचायतों (9892 पुरानी एवं 1449 नयी) में से अधिकतर ग्राम पंचायतों पर ग्रामीण क्षेत्र में कुल 10 हजार से अधिक वाइफाइ हॉटस्पॉट के माध्यम से वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

राजस्वॉन

भारत सरकार द्वारा मार्च, 2005 में देश भर के प्रत्येक राज्य में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा एनईजीपी की परियोजना के भाग के रूप में राज्य में डाटा, टेलीफोन और वीडियो संचार की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परिकल्पित किया गया

है। विभाग में राजस्वॉन परियोजना फरवरी, 2013 से निष्पादित की जा रही है। वर्तमान में राजस्वॉन नेटवर्क में 273 पॉइन्ट ऑफ प्रजेन्स स्थापित किये गए हैं जो राजस्थान राज्य में स्थित क्रमशः राज्य मुख्यालय से संभागीय मुख्यालयों, उनके जिला मुख्यालयों और उनके उपखंड मुख्यालयों से जुड़े हुए कार्यालयों का डाटा, टेलीफोन और वीडियो ट्रेफिक ले जाने की सुविधा प्रदान करता है।

राज ई-वॉलेट

राज ई-वॉलेट के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा दी जा रही है। यह आधिकारिक दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों के साथ-साथ नागरिक के व्यक्तिगत दस्तावेज को सुरक्षित रखने का पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कागजी कार्यवाही की आवश्यकता को कम करना और अपने प्रमाणपत्र, दस्तावेजों को नागरिकों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना हैं।

राज-काज (इन्टीग्रेटेड राज ई-ऑफिस)

राज्य सरकार के सभी राजकीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्ड, कॉरपोरेशन इत्यादि में विभागीय प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों के हित में राजकाज (इन्टीग्रेटेड राज ई-ऑफिस) परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसमें अवकाश प्रबंधन एवं अवकाश नकदीकरण का आवेदन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरण, डाक प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, राजकीय आवास प्रबंधन आदि को प्राथमिकता दी जा रही है।

सिंगल साइन ऑन (एसएसओ)

राजस्थान सरकार की विभिन्न वेबसाइट्स एवं एप्लीकेशन्स का उपयोग करने के लिए सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) बनाया गया है। इसके फलस्वरूप अलग-अलग यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं हैं और एक ही स्थान पर विभिन्न एप्लीकेशन्स का उपयोग सुगमता से किया जा सकता हैं। इसके माध्यम से राजस्थान सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, ई-मित्र संचालकों, निवेशकों एवं नागरिकों को अब एक डिजिटल पहचान दी जा रही है, जिसकी सहायता से उपयोगकर्ता विभिन्न विभागों की ऑनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) के अंतर्गत अभी तक लगभग 2.51 करोड़ आइडेंटिटी एवं 250 जीटूजी, 161 जीटूसी और जीटूबी एप्लिकेशंस भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (आर.एस.डी.सी)

राजस्थान राज्य डाटा सेंटर राज्य के विभागों, एजेंसियों को सक्षम करने हेतु एवं सेवाओं की सुलभ उपलब्धता करने हेतु अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए कुशल इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करता है। यह डाटा सेंटर डाटा प्रबंधन, केंद्रीय संग्रह, आईटी प्रबंधन, संचालन और रखरखाव की समग्र लागत को कम करने के लिए अग्रणी एवं सामान्य बुनियादी ढांचे पर अपनी सेवाओं, अनुप्रयोगों की मेजबानी करता है। आर.एस.डी.सी. के पास 800 रैक की कुल क्षमता-4 डाटा सेंटर, जयपुर और 1 डीआर साइट, जोधपुर में स्थापित है। आर.एस.डी.सी.-पी4 में 600 रैक अपटाइम टियर-4 डिजाइन प्रमाणित हैं, जो 99.995 प्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित करता है। यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डाटा सेंटर है। इसमें 500 से अधिक वेबसाइटों की होस्टिंग की जाती है। यह अत्याधुनिक इंजीनियरिंग मशीनों जैसे -आईबीएम प्यूरएप, ओरेकल ऐक्साडाटा, ओरेकल एक्सलॉजिक, माइक्रोसॉफट एज़्योर और सुरक्षा उपकरण जैसे फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, डीडीओएस, डब्ल्यूएएफ, डैम, एसआईईएम, एपीटी एवं फोरेंसिक आदि से संपन्न है। मुख्यमंत्री के बजट भाषण 2021-22 के क्रम में, राज्य सरकार ने स्टेट डाटा सेंटर की सेवाओं को अन्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभागों, पीएसयू, एजेंसी, संगठन, स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्रों को सशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है।

बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम

प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम विकसित किया गया है। यह आईटी आधारित वर्कफ्लो सिस्टम है, जो आवेदन जमा करने से लेकर, अनुमति पत्र प्रदान करने तक का संपूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है। सिस्टम में बिल्डिंग प्लान स्क्रूटनी इंजिन शामिल हैं जो पूर्ण स्वचालित तरीके से प्रस्तुत किए गए मॉडल की भवन निर्माण नियमों के आधार पर जाँच रिपोर्ट जारी करता है। एप्लिकेशन को एस.एस.ओ. एवं सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा विवरण मिल सके। सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा ऑनसाइट निरीक्षण के लिए एक मोबाइल एप भी विकसित किया गया है। डेशबोर्ड और एनालिटिकल टूल के माध्यम से सिस्टम की निगरानी और निर्णय लिए जाते हैं। उक्त सिस्टम को राज्य के 3 विकास प्राधिकरणों एवं राज्य की 14 यूआईटी और 216 यूएलबी में लागू किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एनओसी सुविधा को भी इस प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

सुशासन और पारदर्शिता के लिए आईटी के प्रयोग में राजस्थान अग्रणी

राजस्थान डिजिटल सिरमौर, आईटी नवाचारों से निखर रही प्रदेश की तस्वीर

"सुशासन, प्रशासन और आमजन के लिए हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आईटी के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के नवाचारों से प्रदेश में ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस तक का सफर उल्लेखनीय रहा है। इन नवाचारों से मिली सफलता के बाद प्रदेशवासियों का जीवन भी आसान हुआ है। राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जबावदेही सुशासन के लिए प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग कर आमजन के लिए कई अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रही है। राज्य सरकार निरन्तर 'हर हाथ तरक्की' और 'टेक्नोलॉजी फॉर ऑल' के विजन के साथ दूरगामी और सुखद परिणाम देने वाले कई बड़े फैसले ले रही है।"

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से
निदेशक (जनसंपर्क) पुरुषोत्तम शर्मा व जनसंपर्क अधिकारी सुरेन्द्र सामरिया द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश...

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत ने दुनिया में खास पहचान बनाई है, इस पूरे परिदृश्य में राजस्थान को कहां देखते हैं?

भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने हमारे देश को एक नई ताकत के साथ 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा। यह श्री राजीव गांधी की दूरदर्शिता थी कि देश की उन्नति के लिए उन्होंने आईटी की भूमिका को बहुत पहले ही पहचान लिया। राजीव जी की वैज्ञानिक सोच तथा दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि आज दुनिया में भारत देश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सबके सामने खड़ा है। उन्हीं के नक्श-ए-कदम पर चलते हुए राजस्थान भी आईटी के क्षेत्र में पूरे देश में सिरमौर बन गया है। आज राजस्थान डिजिटल सर्विस डिलीवरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, दस्तावेजों के ऑनलाइन संधारण जैसे अनेक क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बन गया है। आईटी के जरिए ही हमारी सरकार योजनाओं और कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति कर रही है। अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) से योजनाओं का लाभ भी सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है।

गुड गवर्नेंस को राज्य सरकार ने परम ध्येय बनाया है। यह उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा रहा है?

राज्य सरकार बनने के पहले दिन से ही सुशासन हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। गुड-गवर्नेंस हमारी मंजिल ही नहीं, यात्रा भी है। गुड-गवर्नेंस की इस यात्रा को हम ई-गवर्नेंस से ही पूरी कर रहे हैं। 'सूचना तकनीक से सुशासन' मूल मंत्र को आधार बनाकर राज्य सरकार योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का कार्य कर रही है। धरातल पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन फीडबैक से जनता और सरकार के बीच संवाद बढ़ा है।

सुशासन की इस यात्रा में राज्य सरकार का अगला पड़ाव क्या है?

राज्य सरकार चाहती है कि राजस्थान आईटी आधारित सुशासन में देश का अव्वल राज्य बने। इसके लिए सरकारी सेवाओं का लाभ तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-ढ़ाणी तक त्वरित गति से पहुंचाने में आईटी का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। राजकीय नियुक्तियों की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण

तथा निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों में टेंडर प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने से लेकर डीबीटी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, डिजिटल शिक्षा की पहुंच ढ़ाणी-मगरे तक पहुंचाने सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कई आईटी प्लेटफॉर्म विकसित किये हैं।

सुशासन और पारदर्शिता के लिए योजनाओं को ऑनलाइन किया, यह पहल कितनी सार्थक रही?

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही हर व्यक्ति को सीधे सरकार से जोड़कर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया था। पूरी प्रतिबद्धता से प्रदेशवासियों के बीच 'जनकल्याण' और 'जनसूचना' पोर्टल लॉन्च कर उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। आईटी के जरिए प्रदेश के नागरिकों को उनका हक मिलना सुनिश्चित हो, इसकी नींव हमारी सरकार ने 'राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011' और 'राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012' के साथ ही रख दी थी। इसके तहत विभिन्न विभागों की नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में हर विभाग की हर गतिविधि पारदर्शिता के साथ सबके सामने उपलब्ध है।

डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी में राज्य कैसे आगे बढ़ रहा है?

योजनाओं की डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी में राजस्थान देश में अब सिरमौर राज्य बन गया है। राज्य में लगभग 86 हजार ई-मित्र एवं 15 हजार ई-मित्र प्लस सहित राजीव गांधी सेवा केंद्रों के रूप में पंचायत स्तर तक एक वृहद नेटवर्क उपलब्ध है। राज्य में कुल एक लाख ई-मित्र संचालित हैं, जबकि देश में यह आंकड़ा 3 लाख है। ऐसे में राजस्थान में पूरे देश के एक तिहाई ई-मित्र संचालित हो रहे हैं। ई-मित्र के माध्यम से प्रदेशवासियों को उनके घर के नजदीक 500 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई-शिक्षा, ई-कॉमर्स, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा परामर्श भी ई-मित्रों के जरिए उपलब्ध हो रहा है। अब डिजिटल क्रांति में योजनाएं पोर्टल के साथ ही मोबाइल एप पर भी उपलब्ध हैं, जिनसे सिस्टम में पारदर्शिता बड़ी है।

'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' की चर्चा देशभर में है। इसकी सफलता में आईटी की भूमिका कितनी अहम है?

'निरोगी राजस्थान' की व्यापक संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत हर प्रदेशवासी को 5 लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा दिया था। इसकी सफलता और आमजन की जरूरतों को देखते हुए इस बीमा को अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दिया है और साथ ही 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी दिया है। इस योजना का संचालन और प्रबंधन मूलत: सूचना प्रौद्योगिकी पर ही आधारित है। इसमें हर पात्र व्यक्ति का एक यूनिक आईडी नम्बर होता है जिसमें ई-वॉलेट के रूप में सरकार की ओर से 10 लाख रुपये की राशि जमा रहती है। पात्र व्यक्ति जितनी राशि की चिकित्सा सुविधा लेता जाता है, ई-वॉलेट से उतनी राशि स्वत: ही कम होती जाती है। इससे लाभार्थी को उसके वॉलेट में शेष राशि की जानकारी भी रहती है और पारदर्शिता भी बनी रहती है। योजना से जुड़े चिकित्सालयों की निगरानी में भी आईटी का उपयोग किया जा रहा है। राज्य कर्मियों के लिए लागू की गई आर.जी.एच.एस. योजना की क्रियान्विति भी आई.टी. के द्वारा ही की जा रही है।

राजस्थान आईटी आधारित सुशासन में देश का अव्वल राज्य बने। इसके लिए सरकारी सेवाओं का लाभ तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-ढाणी तक त्वरित गति से पहुंचाने में आईटी का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। राजकीय नियुक्तियों की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण तथा निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों में टेंडर प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने से लेकर डीबीटी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, डिजिटल शिक्षा की पहुंच ढाणी-मगरे तक पहुंचाने सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कई आईटी प्लेटफॉर्म विकसित कर लिए हैं।

कोविड-19 महामारी का सामना करने में डिजिटल माध्यमों की महत्त्वपूर्ण भूमिका कैसे रही?

कोविड-19 महामारी का एक लम्बा समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। राज्य सरकार ने 500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आमजन और समाज के हर विशिष्ट वर्ग से निरंतर संवाद किया। चिकित्सा विशेषज्ञों की राय को अनेक बार लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इस माध्यम का उपयोग किया। इसका सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दिया। गांव-ढाणी से शहरों की घनी आबादी वाली कॉलोनियों तक की परिस्थितियों की जानकारी लेकर सरकारी सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाया। क्वारंटीन सुविधाओं के प्रबंधन, प्रवासी मजदूरों के आवागमन, 24 घंटे वॉर रूम के संचालन, जरूरतमंदों तक राशन सामग्री के वितरण, दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों के प्रबंधन के साथ ही लॉकडाउन के दौरान रोजगार खोने वाले मजदूर वर्ग और ठेले-रेहड़ी वालों के सर्वे में भी आईटी का भरपूर उपयोग किया गया। लगभग 35 लाख लोगों के खातों में आर्थिक सहयोग राशि भी डीबीटी के माध्यम से भेजी गई।

युवाओं को आईटी की नवीन तकनीकों से जोड़ने और उन्हें नए अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है?

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के जनक श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर जयपुर में 'राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी' (आर-कैट) की शुरुआत की है। यहां प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत एवं नवीन प्रौद्योगिकी सीखने का अवसर मिलेगा। इस सेंटर में युवाओं को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण मिल रहा है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और वे राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगे। तकनीकी शिक्षा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जोधपुर में 400 करोड़ रुपये लागत से 'राजीव गांधी फिनटैक इंस्टीट्यूट' का निर्माण होगा। संभागीय मुख्यालयों पर भी आईटी एजूकेशन के संस्थान स्थापित किए जाएंगे। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के बाद कोटा, बीकानेर, चूरू में वर्ल्ड क्लास इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। यहां स्टार्टअप्स को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं मिल रही हैं। जयपुर में 200 करोड़ रुपये लागत से डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में 'राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग' की स्थापना की जा रही है। युवाओं को नई तकनीक से रूबरू कराने के लिए आई.टी. दिवस पर राजस्थान इनोवेशन विजन (राजीव) और डिजीफेस्ट आयोजित किया गया। स्टार्टअप तथा आई.टी. के क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए युवाओं को राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।

कम्प्यूटर शिक्षा आईटी का आधार है। स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कम्प्यूटर शिक्षकों का नया कैडर बनाया गया है। स्कूली स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए कम्प्यूटर अनुदेशक के 10 हजार से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षा कराई गई। इसके परिणाम भी जारी हो गए हैं। जल्द ही राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। हमारे ऐसे ही कई प्रयास भविष्य में राजीव गांधी की सोच का प्रतिबिंब बनकर चमकते नजर आएंगे।

हाल ही राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति की गई है, इनकी गुड गवर्नेंस में क्या भूमिका होगी?

राजीव गांधी युवा मित्र समृद्ध राजस्थान के निर्माण में व्यापक भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, कृषि, सड़क, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में कई फ्लैगशिप योजनाएं चला रही है। युवा मित्र प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं।

राज काज के लिए आईटी नवाचारों से किस तरह सहायता मिल रही है?

समय, धन और संसाधनों की बचत के लिए आईटी आधारित एवं पेपरलेस गवर्नेंस आज की जरूरत है। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वित्त विभाग द्वारा एनआईसी के सहयोग से पेंशन एवं लेखा प्रणाली के सरलीकरण के लिए ई-पेंशन तथा ई-लेखा प्रणाली की शुरुआत की गई है। इससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को जटिलता भरे 40 पृष्ठों के प्रपत्र भरने की औपचारिकता से निजात मिली है। कार्मिकों के वेतन, मेडिकल, यात्रा आदि बिलों, संवेदकों के भुगतान सहित अन्य लेखा कार्यों में सुगमता आई है। पिछले कार्यकाल में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) शुरू की गई थी। ई-कुबेर, पे-मैनेजर, ई-ग्रास, राजकोष आदि सॉफ्टवेयर से वित्तीय प्रबंधन को और सशक्त बनाया गया है। ई-गवर्नेंस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को ई-गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

सरकारी सूचनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या हैं?

सूचनाओं और जानकारियों से ही नागरिक सशक्त बनता है। इसके लिए जन सूचना पोर्टल शुरू किया गया। वर्तमान में जन सूचना पोर्टल पर 115 विभागों में संचालित 326 योजनाओं की 686 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। पोर्टल से लगभग 11.50 करोड़ विजिटर द्वारा विभिन्न सेवाओं की लगभग 15.19 करोड़ सूचनाएं प्राप्त की गई हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार की योजनाओं, सेवाओं, गतिविधियों, सरकारी निर्णयों, उपलब्धियों आदि की नवीनतम जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए जनकल्याण पोर्टल शुरू किया गया है।

प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने में आईटी कितनी उपयोगी साबित हुई है?

प्रदेश के 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन डीबीटी के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। बुजुर्ग, दिव्यांग और असहायों को अब जगह-जगह चक्कर नहीं काटना पड़ता। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब 'ई-मित्र एट होम' भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। पिछले कार्यकाल में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों की स्थापना की गई थी। आज इन केंद्रों पर विभिन्न विभागों की 500 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। शिकायतों के शीघ्र निराकरण में संपर्क पोर्टल प्रभावी साबित हुआ है और पारदर्शिता के कारण यह काफी लोकप्रिय भी हो गया है। ऑनलाइन माध्यम से प्रशासनिक कार्यों, भुगतान, हैल्थ रिकॉर्ड एवं रेवेन्यू रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन, छात्रवृत्ति वितरण आदि में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है।

पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए सूचना तकनीक का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है?

सभी जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनमें अब तक लगभग 7800 ऑनलाइन एवं 480 ऑफलाइन कैमरे लगाकर हर क्षेत्र की सतत निगरानी की जा रही है। अब एफ.आई.आर., पुलिस सत्यापन, आर्म्स लाइसेंस, चालान प्रक्रिया सहित कई कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं।

लगभग 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने का क्या उद्देश्य है?

जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसमें लगभग 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जिसके माध्यम से लाभांवित परिवार की महिला घर बैठे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ ऑनलाइन भुगतान कर सकेगी, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्राप्त कर सकेगी, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज एवं वीडियो कॉल जैसी सुविधा का लाभ भी ले सकेंगी। कोविड जैसी परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है।

जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर सरकार और किस तरह के प्रयास कर रही है?

ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा व बुजुर्ग सदस्य ही हैं, वे सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहें, इसके लिए 'मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना' लायी जाएगी। इसमें ऐसे चिह्नित परिवार Toll Free CM Helpline-181 पर फोन करेंगे तो 'सेवा प्रेरक' (Service Facilitator) घर जाकर उनकी मदद करेंगे। सेवा प्रेरक राशन के लिए नाम जोड़ने, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने, पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने, पालनहार सहित अन्य योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को जोड़ने और उन्हें योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

आपने बजट घोषणाओं में दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन को समाप्त किया। यह कैसी सुविधा है?

प्रदेशवासियों को जवाबदेही एवं पारदर्शिता के साथ समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से दस्तावेजी एवं भौतिक सत्यापन की व्यवस्था को समाप्त किया गया। डिजिटल वैरिफिकेशन आधारित ऑटो अप्रूवल तथा डीम्ड अप्रूवल प्रणाली विकसित की हैं। पात्र लाभार्थियों की किसी अन्य पर निर्भरता समाप्त करने की दृष्टि से ऑटो सिस्टम को बाध्यकारी करने के लिए 'राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट' लाया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता देते हुए निरीक्षण प्रणाली को समाप्त करने की दृष्टि से विभिन्न विभागों में अनावश्यक निरीक्षण की प्रथा समाप्त कर कम्प्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड एनालिसिस के आधार पर रेंडम रोस्टर से अधिकारियों का चयन कर ही निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं, अब समस्त योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है।

साइबर क्राइम वर्तमान में एक बड़ी चुनौती है। आमजन ही नहीं अच्छे-खासे शिक्षित नागरिक भी ठगे जा रहे हैं। राज्य सरकार कैसे सामना करेगी?

सभी विभागों की वेबसाइट की थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट कराई जाती है। सरकार ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रही है जिससे साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके लिए साइबर विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा रही है। प्रशासन एवं पुलिस के नवनियुक्त एवं वरिष्ठ अधिकारियों को साइबर सिक्योरिटी आधारित प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि वे बैंक खाता, ओटीपी सहित गोपनीय दस्तावेज, नंबर आदि किसी से भी साझा नहीं करें और अलर्ट रहें।

प्रदेशवासियों को क्या संदेश देंगे?

राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि वे सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दें। युवाओं से कहूंगा कि वे विभिन्न आईटी सेंटर्स में जाकर नवीन तकनीक का प्रशिक्षण लें और राज्य की प्रगति में अहम भूमिका निभाएं।

अवॉर्ड

- **राज्य में स्टार्टअप हेतु मजबूत वातावरण के लिए Ministry of Commerce and Industries, GoI द्वारा वर्ष 2022 में States' Startup Ranking 2021 सर्टिफिकेट।**
- **बेहतरीन Document Verification Mobile APP के लिए IMC Digital Technology Awards 2021 में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित।**
- **Document Verification and Authentication Engine के Best Digital Implementation के लिए IMC Digital Technology Awards 2020 में Award for Excellence से सम्मानित।**
- **Rajmasters Application के लिए IMC Digital Technology Awards 2020 में Best Digital Implementation का सर्टिफिकेट।**

सूचना तकनीक के उपयोग से घर बैठे सरकारी विभागों की समस्त सेवाओं की पहुंच सुलभ करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

“मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा है कि आमजन को सुशासन मिले। सूचना तकनीक के उपयोग से घर बैठे सरकारी विभागों की समस्त सेवाओं की पहुंच सुलभ करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रकार की नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, सभी विभाग अपनी समस्त योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां जन सूचना पोर्टल पर साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। आईटी का उपयोग कर पारदर्शिता एवं सुशासन के लिए पहल करने वाला राजस्थान अन्य प्रदेशों के लिए मॉडल स्टेट बन रहा है।”

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री अखिल अरोरा से
अतिरिक्त निदेशक (जनसंपर्क) अलका सक्सेना द्वारा की गई बातचीत के महत्त्वपूर्ण अंश...

सुशासन को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए सूचना तकनीक का उपयोग महत्त्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार इस दिशा में किस तरह के प्रयास कर रही है?

जो लोग जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में जागरूक बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा है कि आमजन को सुशासन मिले। सूचना तकनीक के उपयोग से घर बैठे सरकारी विभागों की समस्त सेवाओं की पहुंच सुलभ करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रकार की नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, सभी विभाग अपनी समस्त योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां जन सूचना पोर्टल पर साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। आईटी का उपयोग कर पारदर्शिता एवं सुशासन के लिए ऐसी पहल करने वाला राजस्थान अन्य प्रदेशों के लिए मॉडल स्टेट बन रहा है।

स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार किस तरह के कार्य कर रही है?

विभाग द्वारा अब तक लगभग 300 स्टार्टअप्स को लगभग 15 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है। गत वित्तीय वर्ष में भी विभिन्न तरह के 171 स्टार्टअप्स को 9.5 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। राज्य में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को विभिन्न विभागों में चयनित कार्यों के लिए 15 लाख रुपए तक के कार्यादेश बिना टेंडर प्रणाली के देने का निर्णय किया गया है। इससे स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।

स्टार्टअप गतिविधियां अक्सर शहरों तक ही सीमित रहती हैं। प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को इससे जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार की क्या योजना है?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं एवं विद्यार्थियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संभाग स्तर पर इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित करने तथा स्कूल स्तर तक स्टार्टअप्स गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार स्टार्टअप्स गतिविधियों को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहे, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। आई-स्टार्ट की तर्ज पर रूरल आई-स्टार्ट कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा खोले गए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों, इनोवेटर्स, ग्रामीण उद्यमियों आदि को इनसे विशेष तौर पर जोड़ने के प्रयास रहेंगे। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के साथ-साथ अब ग्रामीण और

स्कूली छात्रों के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जो प्रदेश की आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। प्रदेश में स्कूली बच्चों के स्टार्टअप को 10 हजार से 1 लाख रुपये व ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विभाग का यह नवाचार स्कूली बच्चों और ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करेगा।

आईटी सेक्टर को मजबूत करने के लिए 650 करोड़ रुपये की लागत से फिनटैक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। यह किस तरह का संस्थान होगा?

जोधपुर में 650 करोड़ रुपये की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी का निर्माण जारी है। फाइनेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर बन रही देश की अपनी तरह की पहली राजीव गांधी फिनटैक डिजिटल यूनिवर्सिटी में एक साथ 31 पाठ्यक्रम संचालित होंगे, जो प्रमुख रूप से फाइनेंस व टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे। इन पाठ्यक्रमों से साल भर में 4000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा संभागीय मुख्यालयों पर भी राजीव गांधी के नाम से आईटी शिक्षा के संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड प्रबंधन में किस तरह की भूमिका निभाई?

कोविड के दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 500 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। महत्त्वपूर्ण सूचनाओं, दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रबंधन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों और विशिष्टजनों को जोड़ने के साथ-साथ राजधानी से लेकर जिला तथा गांव-ढ़ाणी स्तर तक वीसी के जरिए लगभग 6500 बैठकों और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन भी विभाग के माध्यम से किया गया है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमितों की भर्ती, होम क्वारंटीन सुविधाओं, प्रवासियों के आवागमन, मजदूरों के रजिस्ट्रेशन, जरूरतमंद परिवारों एवं व्यक्तियों की आर्थिक मदद के लिए बैंक खातों में नकद राशि के हस्तान्तरण, रोगियों-संक्रमितों के लिए हेल्पलाइन जैसे अतिआवश्यक कार्यों को भी अंजाम दिया गया।

विभाग की ओर से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (आर-केट) की शुरुआत की गई है। यह सेंटर क्या है और युवाओं के लिए किस तरह लाभदायक सिद्ध होगा?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। इससे प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत व उभरती प्रौद्योगिकी सीखने का अवसर मिल रहा है। इन क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों के विशेषज्ञों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे युवाओं को रोजगार के उत्कृष्ट अवसर मिलेंगे और वे राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगे। उन्नत उपकरणों, अनुभवी प्रशिक्षकों व विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त संस्थान में ओरेकल, वीएम वेयर, एसएएस, रेडहैट, सिस्को, अटोफिना जैसी विश्वस्तरीय आईटी कंपनियां ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं। वर्तमान में 185 विद्यार्थी संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नि:शुल्क लाभ ले रहे हैं। यह सेंटर युवाओं, कामकाजी पेशेवरों व सरकारी कर्मचारियों को आईटी उद्योग की मांग के अनुसार तैयार करने के लिए जरूरी तकनीकी स्किल्स सिखाने में फिनिशिंग स्कूल के रूप में कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। इससे प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत व उभरती प्रौद्योगिकी सीखने का अवसर मिल रहा है। इन क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों के विशेषज्ञों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे युवाओं को रोजगार के उत्कृष्ट अवसर मिलेंगे और वे राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगे। उन्नत उपकरणों, अनुभवी प्रशिक्षकों व विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त संस्थान में ओरेकल, वीएम वेयर, एसएएस, रेडहैट, सिस्को, अटोफिना जैसी विश्वस्तरीय आईटी कंपनियां ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं। वर्तमान में 185 विद्यार्थी संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नि:शुल्क लाभ ले रहे हैं।

स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर्स की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में इन्हें कहां-कहां तैयार किया जा रहा है?

जयपुर के झालाना क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार का डाटा सेंटर पूरे देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर्स में से एक है। जयपुर के टेक्नो हब में संचालित डिजिटल म्यूजियम में आमजन को नवीन एवं रोचक जानकारियां मिल रही हैं। राजधानी जयपुर की तरह अन्य छह संभागीय मुख्यालयों पर हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित इनक्यूबेशन सेंटर्स तैयार किए गए हैं। संभागीय मुख्यालयों के अतिरिक्त पाली और चूरू में इनक्यूबेशन सेंटर्स बनकर तैयार हैं। टेक्नो हब प्रदेश की तकनीकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगे और इनक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा।

साकार होंगे आत्मनिर्भरता से स्वर्णिम भविष्य के स्वप्न

देश-दुनिया में पहचान बनाएगा जोधपुर का इन्क्यूबेशन सेंटर

रंग ला रहे हैं युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकासपरक महत्त्वाकांक्षी प्रयास

आकांक्षा पालावत
जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान सरकार हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र में रोज़गारोन्मुखी योजनाओं और आत्मनिर्भरतापरक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और रचनात्मक विचारों को पुष्पित-पल्लवित करते हुए समुचित सुविधाएं और उपयुक्त वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर स्तर पर भरसक प्रयासों में जुटी हुई है। प्रदेश के युवाओं को सुनहरा भविष्य प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार किए जा रहे यह प्रयास रंग ला रहे हैं।

इसी दिशा में पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े और तीव्रता से प्रगतिशील जोधपुर संभाग के युवाओं को उनके रचनात्मक आइडियाज को प्रोत्साहित करते हुए व्यवसाय के प्रारंभिक दौर में हरसंभव सहयोग, मार्गदर्शन और माहौल देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का प्रदेश के लिए बहुत बड़ा तोहफा है।

जोधपुर संभाग मुख्यालय के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा कुल 13.5 करोड़ की लागत से बन रहे इस इनक्यूबेशन सेंटर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस इनक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा आई स्टार्ट योजना का संचालन किया जा रहा है। जोधपुर में आईआईटी, एनआईएफडी, एनएलयू, एम्स जैसे विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न शिक्षण संस्थान संचालित हैं, जहां के विद्यार्थी अपने रचनात्मक नवाचारों के साथ देश-दुनिया के लिए नवीन सृजनात्मक उद्यमों को विकसित करने की क्षमताओं को विकसित करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में उन्हें आवश्यकता है बेहतर सकारात्मक माहौल, उपयुक्त मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, सुविधाओं और आर्थिक सम्बल की, जो उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर्स पर उपलब्ध होगा, और वह भी नि:शुल्क।

इनक्यूबेशन सेंटर – उद्देश्य और लक्ष्य

स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मददगार सिद्ध होने वाले संस्थानों को इनक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप के लिए संजीवनी के समान होते हैं। यह संस्थान आम तौर पर स्टार्टअप्स को व्यापारिक एवं तकनीकी सुविधाओं, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि नेटवर्क और कनेक्शन, सहकारी रिक्त स्थान, प्रयोगशाला की सुविधा, सलाह और सलाहकार समर्थन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

मार्गदर्शक गुरु की भूमिका में हैं ये इनक्यूबेशन सेंटर

जीवन के समग्र विकास की दृष्टि से एक समर्थ गुरु और मार्गदर्शक की भूमिका में यह इनक्यूबेशन सेंटर्स किसी भी स्टार्टअप को उचित मार्गदर्शन और सही वातावरण देकर उनके व्यवसाय के प्रारंभिक चरण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनक्यूबेशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाएं और माहौल इन स्टार्टअप के लगभग सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) का हिस्सा होते हैं। यदि देखा जाए तो इनक्यूबेशन एक प्रक्रिया के रूप में काम करता है, जो स्टार्टअप विचार (स्टार्टअप आइडिया) को असफल (फैलियर) होने के हर संभव खतरे से बचाता है तथा उन्हें सफल होने में आने वाली बाधाओं को पार करने में मदद करता है।

स्टार्टअप नीति के तहत इनक्यूबेशन सेंटर की भूमिका

स्टार्टअप इंडिया स्कीम में इनक्यूबेशन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के तहत सरकार ने स्टार्टअप, समर्थन और सपोर्ट के उद्देश्यों को साकार करने के लिए स्टार्टअप के लिए देश में प्रतिष्ठित इनक्यूबेशन सेंटर को मान्यता प्रदान की है। यह इनक्यूबेटर संचालक स्टार्टअप का मूल्यांकन कर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत लाभ प्रदान करने के लिए इनके नाम सरकार को सुझाता है और अवसर प्रदान करता है।

सेंटर में होंगी ये सुविधाएं

जोधपुर में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित होने से न केवल संभाग भर में बल्कि आस-पास के युवाओं को एक ही स्थान पर बड़े महानगरों की भांति बेहतरीन स्टार्टअप वातावरण उपलब्ध होगा। इस सेंटर में आई स्टार्ट के चयनित स्टार्टअप्स को अपने उद्यम को आगे बढ़ाने और उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह आधुनिक एवं पूर्णतया वातानुकूलित इनक्यूबेशन सेटअप होगा, जहां स्टार्टअप्स को हाई-स्पीड इंटरनेट, मीटिंग रूम, टिंकरिंग लैब, अडिटोरियम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एवं मेंटर्स इन स्टार्टअप्स को परामर्श देकर उनके बिजनेस आइडिया के सफल क्रियान्वयन में मदद करेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप्स को सीड फंड, सस्टेनेन्स अलाउंस, मार्केटिंग अलाउंस जैसे विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध हो सकेंगे ताकि उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में हर स्तर पर हर प्रकार का सम्बल प्राप्त हो सके। युवाओं को नवाचारपरक उद्यमशीलता एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर हर क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

क्या है आई स्टार्ट

राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की फ्लैगशिप योजना है istart ..इसके अंतर्गत istart.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाने पर स्टार्टअप्स को उनके रचनात्मक आइडियाज पर चयनित किया जाता है। यह रजिस्ट्रेशन पूर्णतया नि:शुल्क है, इसके बाद चयनित स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय के पहले वर्ष तक इन्क्यूबेशन सेंटर की सभी सुविधाएं एवं मार्गदर्शन नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। एक वर्ष के बाद सरकार की न्यूनतम दरों पर स्टार्टअप्स को समुचित सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है।

जोधपुर का इनक्यूबेशन सेंटर बनकर तैयार है। आगामी कुछ समय में यह शहर के नए स्टार्टअप्स और नवाचारों का केंद्र होगा। चूँकि किसी भी नए व्यवसाय की नींव डालने के प्रारंभिक दौर में सबसे बड़ी दिक्कत वर्किंग प्लेस और संसाधनों की होती है। काम शुरू होने से पहले ऑफिस स्पेस के किराये, संसाधनों की खरीद, बिजली का बिल, स्टाफ की तनख्वाह आदि के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता भरी दरकार होती है। नवाचारों को व्यवसाय को धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान सरकार इनक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से स्टार्टअप्स को ये सभी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवाती है, वो भी नि:शुल्क। जोधपुर के इनक्यूबेशन सेन्टर में शुरुआती दौर में 75 लोगों के बैठने की सुविधा दी गयी है, जिसे आगामी समय में और बढ़ाया जा सकता है। बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए के लिए मेंटर लगाए गए हैं। साथ ही आईडिया चुने जाने पर हर माह ग्रांट मिलेगी। 25 आईडियाज चयनित होने पर 25 लाख का ऋण भी न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जायेगा। जोधपुर के सेंटर से 50 स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं। यह स्टार्टअप्स शिक्षा, कृषि, आईटी, पर्यटन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल आदि क्षेत्रों में नवाचार करके अपने बिज़नेस आईडियाज को क्रियान्वित कर स्वाभिमान और सम्मान के साथ प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान कायम करने की दिशा में निरन्तर प्रगति पर हैं। जोधपुर का यह इनक्यूबेशन सेंटर आने वाले समय में देश-दुनिया में अपनी अनूठी पहचान के साथ राजस्थान को गौरव प्रदान करने वाला सिद्ध होगा।

World Class Finishing School

Rajiv Gandhi Center of Advanced Technology (R-CAT)

Jyoti Luhadiya
Additional Director, DOIT&C

Rajasthan has taken a leapfrog strategy in various areas, including technology, vocational education, and start-up ecosystem. The State Government under the dynamic leadership of Chief Minister Shri Ashok Gehlot is determined to enrich the employability opportunities for the undergraduates/ graduates/ postgraduates of the state, resulting in the announcement of Rajiv Gandhi Center of Advance Technology (R-CAT) in the state budget of FY 2021-2022. R-CAT is a Government of Rajasthan undertaking.

Executing the budget announcement, Shri Ashok Gehlot inaugurated the Rajiv Gandhi Center of Advanced Technology in Jaipur on August 20, 2022. He said that the center would give an opportunity to the youths of the state to learn advanced and emerging technologies in fields like Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cyber Security, Robotics, Machine Learning and Data Analytics. Youths will be trained by experts from IT majors. This will create excellent employment opportunities which will help youth play an important role in the development of the state. He said that it is the state government's objective to ensure that the benefits of the public welfare schemes reach the remotest part of the state through adopting advance and emerging IT systems.

The Chief Minister said that the inauguration of R-CAT is a glowing tribute to the father of India's IT revolution Shri Rajiv Gandhi on his birth anniversary. Shri Rajiv Gandhi had a version of bringing the country into the category of developed nations through IT. It is the result of his vision that the world today recognises the talent of Indian youth in the field of IT. Shri Gehlot took a round of the institute and interacted with the students and faculties.

Praising the work of companies providing advanced training to the students at the institute, Shri Gehlot said the state government was working with them in an excellent tandem. More companies will be linked to the institute soon. He said that IT has an important role in providing responsive, transparent and accountable administration. Information about various government schemes is now easily accessible to the general public through the Jan Sampark Portal.

The Chief Minister said that major IT companies like Oracle, VMware, SAS, RedHat, Cisco and Autofina are running training programmes as training partners in the institute with advanced equipment, experienced trainers and world class infrastructure. Further, Chief Minister added that R-CAT will partner with many more global technology giants to offer training & certification in the advance and emerging technologies like Blockchain, AR/VR, IOT, etc.

On the auspicious day of Late Shri Rajiv Gandhi's birth anniversary, the Rajasthan government announced to sponsor first batches of students to pursue advance technology courses of their choice offered by R-CAT. Over 185 students are availing sponsoring benefit of training programmes at the institute presently. The centre is functioning as a finishing school for imparting technical skills to the youth, working professionals and government employees.

About R-CAT

With the purpose to provide cohesive environment for developing quality technical manpower for the industry and government through globally recognized training program leading to reduction of gap between learning and application of technology, R-CAT has been incorporated under Rajasthan

Society Registration Act 1958, in the year 2022, managed under the aegis of Department of Information Technology & Communication (DoIT&C), Government of Rajasthan (GoR).

In collaboration with global tech giants like Oracle, VMWare, SAS, Red Hat etc, R-CAT will conduct training programs on advanced & emerging IT technologies with a duration ranging from one week to six months for professional graduates like BE/B.Tech., BCA, MCA, MBA, and M.Sc. (IT) etc. The targeted technologies would be Artificial Intelligence and Machine Learning (AI-ML), Blockchain, Augmented Reality/ Virtual Reality (AR/VR), Big Data Analytics, Robotics and Quantum Computing etc.

Apart from these domain skills, R-CAT will serve as a finishing school, with the goal of developing soft skills that will lead to overall personality development. As a result, trainees will be more adaptable and employable in the industry.

Key Objectives of R-CAT

- To enhance the employability quotient of the youth (undergraduates/ graduates/ post graduate students) of the state in the field of Information Technology and allied discipline.

- To conduct certificate courses on advanced and emerging technologies like Artificial Intelligence, Machine Learning, Block Chain, Augmented reality/ Virtual Reality, Big Data Analysis, Clinical data analysis, IoT, Robotics, Quantum Computing etc. through Training Partners.
- To act as finishing school for developing technical and soft skills of youth and working professionals to make them Industry ready.
- To conduct research in the field of Information Technology, related enabled services and emerging technologies
- To support start-ups for industry updates, co-working space, utilization of already established labs etc.
- To tie-up with Industry Partners for incessant industry insights and implementation of certificate courses.

समग्र और एकीकृत निगरानी प्रणाली विकसित कर रहा है

अभय कमांड सेंटर

'करीब 550 कैमरों के जरिए 24 घंटे हो रही है बीकानेर शहर की निगरानी'

भाग्यश्री गोदारा
जनसंपर्क अधिकारी

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में नवीनतम तकनीक के जरिए शहरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए अभय कमांड सेंटर मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। बीकानेर शहर में 24 घंटे कार्यरत अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर में सूचना प्रौद्योगिकी और पुलिस द्वारा समन्वित रूप से कार्य किया जा रहा है। समग्र और एकीकृत निगरानी प्रणाली को लागू करने में इस सेंटर के माध्यम से तकनीकी की असाधारण भूमिका को स्थापित किया गया है।

इस सेंटर पर वीडियो सर्विलांस कक्ष, डायल 100 नियंत्रण कक्ष तथा डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। शहर में अभय कमांड सेंटर के 167 पोल्स पर 547 सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे काम कर रहे हैं, पुलिस विभाग के कार्मिकों द्वारा इस सेंटर के माध्यम से 24 घंटे शहर में ट्रैफिक, विभिन्न आयोजनों, आवाजाही सहित समस्त संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाती है। इस सेंटर के लिए शहर में 280 और कैमरे लगाए जाना भी प्रस्तावित है, जिससे निगरानी व्यवस्था और सुदृढ़ हो सकेगी।

अभय कमांड सेंटर में इस तकनीक का प्रयोग व्यापक तौर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ-साथ ट्रैफिक जाम की स्थिति से लोगों को बचाने, धरना प्रदर्शन सहित विभिन्न आयोजनों के दौरान स्थिति पर नजर रखने के लिए भी किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की सहायता से कई शातिर अपराधियों को पकड़ने में मदद मिली है। अभय कमांड सेंटर में उपलब्ध सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से अन्य राज्यों और जिलों से पुलिस अनुसंधान के लिए आने वाली टीमों को भी जांच में सहयोग मिलता है।

अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर में उपलब्ध वीएमएस तथा वीडियो एनालिटिक्स प्रणाली का उपयोग करते हुए पुलिस को अपराधों की जांच अनुसंधान में सहयोग किया जा रहा है इससे कानून व्यवस्था संधारित करने और अपराधियों की धरपकड़ में विशेष मदद मिली है।

जेल की भी हो रही है निगरानी

अभय कमांड सेंटर के जरिए शहर के मुख्य चौराहों, सड़कों, राजमार्गों के साथ- साथ केंद्रीय कारागार की निगरानी भी की जा रही है। इसके लिए जेल परिसर में उच्च गुणवत्ता के 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनका नियंत्रण अभय कमांड सेंटर में किया गया है । शहर में मुख्य रूप से अस्पताल, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड सहित मुख्य मार्गों, चौराहे को भी अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरे से जोड़ा गया है

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर आपराधिक गतिविधियों को रोकने, अपराधियों के मूवमेंट का पता लगाने और उससे निपटने में खासी मदद मिल रही है। बीकानेर पुलिस ने अभय ऐप के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा देने की दिशा में भी एक अहम पहल की है।

आईटी के आसमाँ में जोधपुर की ऊँची छलांग

राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी

डॉ. दीपक आचार्य
उप निदेशक, जनसम्पर्क

- **साकार होने लगे हैं डिजिटल क्रांति के स्वप्न**
- **सूर्यनगरी में उगने लगे हैं नए जमाने के 'सूरज'**

कला-संस्कृति, अनुपम साहित्य, शौर्य-पराक्रम भरे इतिहास और बहुआयामी विकास का अविस्मरणीय परिदृश्य दर्शाने वाला राजस्थान अब अत्याधुनिक सूचना-संचार तकनीक और डिजिटल युग की जरूरतों के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सूचना तकनीक में तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में नये कदम बढ़ा रही है।

राजस्थान में युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की संकल्पनाओं को साकार करने की दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा तमाम संभावनाओं को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर अनथक प्रयास किए जा रहे हैं।

युवाओं के शैक्षिक, प्रशैक्षणिक, सहशैक्षिक विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों, मागदर्शन एवं प्रोत्साहन के लिए आर्थिक सम्बल जैसे कई ऐतिहासिक आयामों के साथ ही वैश्विक जरूरतों के अनुरूप सूचना संचार तकनीक, अत्याधुनिक नेटवर्किंग और डिजिटल विश्व से जोड़ने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह अपूर्व तो है ही, प्रदेश के युवाओं के सुनहरे भविष्य और आईटी क्षेत्र के लिए सरकार का वह तोहफा है जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर जोधपुर में आईआईटी, एम्स, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पुलिस यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थाओं की पहले से मौजूदगी के साथ ही अब डिजिटल यूनिवर्सिटी बनने से जोधपुर देश भर में अपनी तरह के ख़ास डिजिटल पावर हाउस के रूप में उभरकर अपनी पहचान कायम करेगा।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 में घोषित फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना 672 करोड़ की लागत से होने जा रही है। यह राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। केरल के बाद अब राजस्थान भी इसके माध्यम से तकनीकी और डिजिटल युग के नवीन क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है।

राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के देखरेख में फिनटेक जोधपुर जिले में नागौर मार्ग पर करवड़ में आईआईटी के पास यूनिवर्सिटी 41.25 एकड़ क्षेत्रफल में 672.50 करोड़ रुपये में बनाई जा रही राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण मार्च-2024 तक पूर्ण होना निर्धारित है।

इस बहु-उद्देश्यीय यूनिवर्सिटी की स्थापना से समाज-जीवन और प्रदेश-देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास से लेकर सामुदायिक तरक्की के विभिन्न क्षेत्रों को सम्बल प्राप्त होगा।

ख़ासकर प्रशिक्षित मानव संसाधनों की मांग पूरी करने, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, इतिहास, क्षेत्रीय अध्ययन, भाषा, मीडिया व प्रबंधन में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने, शिक्षा, विधि, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, गवर्नेंस, नीति निर्माण जैसे बहुआयामी क्षेत्रों में तकनीक आधारित शोध को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही जोधपुर तथा प्रदेश के युवाओं को आर्थिक, वित्तीय, डिजिटल और तकनीकी विषयों के आधुनिकतम ज्ञान से रूबरू कराने और इन क्षेत्रों में नई पीढ़ी के कौशल विकास की दृष्टि से अप्रत्याशित लाभ एवं आशातीत सफलता हासिल होगी।

विकसित होगा कम्प्यूटिंग का ग्लोबल हब

फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड आईटी (School of Computer Science and IT), फाइनेंस एण्ड अकाउंटिंग, डाटा एनालिटिक्स (Data Analytics) और एनालिटिकल मैथेमेटिक्स जैसे केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

इसके तहत निजी क्षेत्रों के सहयोग से विभिन्न अत्याधुनिक तकनीक आधारित कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई), ब्लॉकचेन, डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, बायो-कम्प्यूटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एण्ड डिसरप्टिंग कन्वेंशन मॉडल ऑफ वर्क एंड बिजनेस जैसे एक्सीलेंस केंद्रों की स्थापना भी प्रस्तावित है।

विश्वविद्यालय का बहुमंजिला भवन अत्याधुनिक व अंतरराष्ट्रीय मानक का होगा जो दूर से ही वर्चुअल दुनिया का आभास करवाने वाला होगा। प्रस्तावित विश्वविद्यालय के नाम में जोड़ा गया शब्द फिनटेक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन को इंगित करता है, अर्थात् विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में तकनीक आधारित वित्तीय सेवाओं के त्वरित आदान-प्रदान पर भी फोकस किया जाएगा।

इसके लिए मांग के अनुसार अतिरिक्त भूमि के आवंटन की कार्यवाही जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग द्वारा संशोधित बजट 672.45 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी है। विभाग द्वारा Soil Testing तथा Geotechnical -Topographical Survey का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा बाउन्ड्री वॉल का निर्माण कार्य प्रगतिरत है जबकि मुख्य भवन का निर्माण शीघ्र ही आरंभ होने जा रहा है। इन कार्यों से संबंधित एस्टीमेट जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जोधपुर विद्युत

वितरण निगम से प्राप्त कर अनुमानित राशि का अग्रिम भुगतान सम्बन्धित विभागों को किया जा चुका है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन

इसमें एक साथ 31 पाठ्यक्रम संचालित होंगे, जो मुख्यतया फाइनेंस व टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे। यूनिवर्सिटी में मुख्य रूप से फाइनेंस की ही पढ़ाई होगी। इन पाठ्यक्रमों से प्रत्येक वर्ष में 4 हजार विद्यार्थी कोर्स करके निकलेंगे। पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। सभी पाठ्यक्रम 4 स्कूलों के मार्फत संचालित होंगे।

इसमें स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इनफॉरमेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एण्ड मार्केट, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स और स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन एण्ड एंटरप्रेन्योरशिप शामिल है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इस बारे में दिए गए प्रजेन्टेशन को देख मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि अपनी तरह का अनूठा यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुर को गौरव प्रदान करेगा।

अत्याधुनिक इमारतें होंगी आकर्षण का केन्द्र

इस विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से एकेडमिक ब्लॉक, वर्कशॉप, गेस्ट हाउस, डीन रेजिडेन्स, फैकल्टी ब्लॉक, नॉन टीचिंग स्टाफ ब्लॉक, हॉस्टल व प्लेग्राउण्ड का निर्माण किया जायेगा। यूनिवर्सिटी में दो एकेडमिक ब्लॉक बनेंगे।

इनमें से प्रत्येक अकादमिक ब्लॉक ग्राउण्ड फ्लोर सहित 8 मंजिला होगा। इसमें 20 स्मार्ट क्लासरूम होंगे। तीन मंजिल की वर्कशॉप बनाई जाएगी, जिसमें विश्वस्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। नौ मंजिल का शिक्षक आवास, 7 मंजिल का गैर शिक्षकों का आवास, तीन मंजिल का निदेशक व डीन का कार्यालय, 9 मंजिल का छात्रावास और 2 मंजिल का गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। सभी इमारतें एक सीध में तीन ब्लॉक में होंगी।

फिनटेक यूनिवर्सिटी का काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल चारदीवारी का काम काफी हद तक हो चुका है। विश्वविद्यालय के लिए सरकार द्वारा प्रथम किस्त के तौर पर प्रदत्त 8 करोड़ रुपये का काम पूरा हो गया है।

3 से 4 साल के होंगे स्नातक पाठ्यक्रम

फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट कार्यक्रम एक साल, स्नातकोत्तर कार्यक्रम 2 साल और स्नातक कार्यक्रम 3 से 4 साल तक के होंगे। प्रत्येक क्लास में 30 अथवा 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। हर साल 10 विद्यार्थी पीएचडी करके निकलेंगे।

इसमें कई सारे महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रमों की सुविधा उपलब्ध होगी। इनमें 7 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, 16 स्नातक पाठ्यक्रम, 8 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और पीएचडी सहित कुल 31 पाठ्यक्रम संचालित होंगे। इस विवि में हर साल 4 हजार विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी।

सूर्य नगरी में स्थापित होने जा रही राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र का परिदृश्य बदलने वाली सिद्ध होगी। आने वाले

समय की मांग और जरूरतों के अनुरूप डिजिटल प्रतिभाओं को निखारने वाली इस यूनिवर्सिटी में विशेषकर साइबर सुरक्षा और तेजी से बदलती तकनीक के साथ ही इंटेलीजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स ऑटोमेशन व कंप्यूटरीकृत उत्पादन पर फोकस किया जाएगा।

डिजिटल यूनिवर्सिटी का ये है नया कंसेप्ट

पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं पर निर्भर होती जा रही है। वित्तीय सेवाओं से लेकर छोटे-बड़े सारे कार्यों के लिए लोगों की अब इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अब साइबर अटैक का खतरा भी पांव पसारने लगा है। इससे निपटने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की पूरी फौज की जरूरतों को यह पूरा करेगी ताकि आने वाले समय में देश के लोगों को साइबर अटैक से बचाया जा सके। वर्तमान में तकनीक के क्षेत्र में निरन्तर होते जा रहे बदलावों के साथ साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सामंजस्य बिठाते हुए नई तकनीक का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए भी जोधपुर में स्थापित हो रही डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी लाभदायी सिद्ध होगी।

इससे दिल्ली, बेंगलुरु, मुम्बई, हैदराबाद, पूणे, चेन्नई आदि महानगरों में संचालित शिक्षण संस्थानों के समकक्ष नई पीढ़ी को लाभान्वित करने की दिशा में सरकार का यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा।

इन पाठ्यक्रमों पर रहेगा फोकस

इस यूनिवर्सिटी में मुख्य रूप से चार पाठ्यक्रमों का संचालन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस(एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मशीन लर्निंग(एमआई), रोबोटिक्स, ऑटोमेशन व कंप्यूटरीकृत मैन्युफैक्चरिंग। अधिकांश पढ़ाई ऑनलाइन होगी। ऐसे में ज्यादा बड़े बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं रहेगी बल्कि प्रैक्टिकल के लिए लैब्स एवं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ही आवश्यकता रहेगी।

स्टार्टअप को मिलेगा बेहतर प्लेटफार्म

वर्तमान में जोधपुर में एम्स, आईआईटी, फैशन इंस्टीट्यूट, फुटवियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, कृषि विश्वविद्यालय, एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एनएलयू, काजरी, आफरी व डेजर्ट मेडिसन रिसर्च सेंटर, रिमोट सेंसिंग सेंटर सहित कई संस्थान हैं। इन सभी के साथ यह एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा सकेगा। साथ ही यहां से निकलने वाले छात्रों के माध्यम से स्टार्ट अप कल्चर को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टार्टअप निखरेंगे और इनका लाभ जोधपुर एवं राजस्थान प्रदेश को मिलेगा।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 में घोषित फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना 672 करोड़ की लागत से होने जा रही है। यह राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। केरल के बाद अब राजस्थान भी इसके माध्यम से तकनीकी और डिजिटल युग के नवीन क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है।

राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के देखरेख में फिनटेक जोधपुर जिले में नागौर मार्ग पर करवड़ में आईआईटी के पास यूनिवर्सिटी 41.25 एकड़ क्षेत्रफल में 672.50 करोड़ रुपये में बनाई जा रही राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण मार्च-2024 तक पूर्ण होना निर्धारित है।

डिजिटल क्रांति का सपना होगा साकार

इस विश्वविद्यालय के माध्यम से नए जमाने के अनुरूप व्यापक तौर पर डिजिटल क्रांति का सपना साकार किया जा सकेगा। इसमें नई तकनीकों पर गहनता से अध्ययन कराया जाएगा। इसके साथ ही इस तकनीक का उपयोग वित्तीय सेवाओं के साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा व उद्योगों में किए जाने लायक बेहतर प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा ताकि इसका लाभ आम आदमी तक तेजी से पहुंच सके। इससे जोधपुर में पहले से विद्यमान कृषि व स्वास्थ्य से जुड़े बेहतरीन संस्थानों को भी तकनीकी लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही औद्योगिक विकास की दृष्टि से समृद्ध जोधपुर में बड़ी संख्या में संचालित उद्योग भी इस नई यूनिवर्सिटी के साथ टाईअप कर अपने उद्योगों को नई तकनीक से अपग्रेड कर सकेंगे।

युवा शक्ति को पारंगत करने में अहम् सिद्ध होगा

फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट युवा शक्ति को डिजिटल एवं सूचना क्रान्ति के माध्यम से नवीन और उभरती टेक्नोलॉजी में पारंगत करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह संस्थान जोधपुर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान के लिए डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

यह विश्वविद्यालय प्रदेश और देश के कई संस्थानों के लिए भी तकनीकी क्षेत्रों में सहयोगी भूमिका अदा करने वाला सिद्ध होगा। राजस्थान को देश तथा दुनिया में यह विश्वविद्यालय गौरव प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा से हो रहे इस तरह के तमाम कार्य सदियों तक अविस्मरणीय बने रहकर लोक कल्याण और बहुआयामी विकास के लिए अनुकरणीय प्रेरणा का संचरण करते रहेंगे।

राजस्थान डिजिफेस्ट

जयपुर में 19-20 अगस्त, 2022 को आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट समारोह के प्रति युवाओं में जबरदस्त आकर्षण देखा गया। समारोह में प्रदर्शित विभिन्न मॉडल्स और कार्यक्रम की झलकियां यहां प्रस्तुत हैं। छाया: सूजस

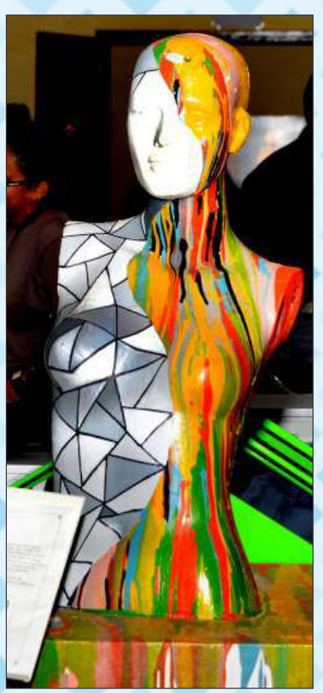

राजस्थान की गौरवमयी गाथा

Some Interesting Facts about Rajasthan

ई–गवर्नेंस तथा एम–गवर्नेंस

राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रान्ति के उत्तरोत्तर बढ़ते कदम

डॉ. गोरधन लाल शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

प्राचीनकाल से ही मनुष्य दूरस्थ व्यक्ति से सम्पर्क हेतु अनेक प्रकार के उपायों को काम में लाता रहा है। पुरातन काल में ढोल या नगाड़ों की सांकेतिक ध्वनियों अथवा सींग के बाजों द्वारा संदेश दिए जाते थे। शांति के संदेशवाहक कबूतरों ने भी संवाद वाहक की भूमिका निभाई। धीरे–धीरे एक व्यवस्थित डाक प्रणाली का विकास हुआ। वैज्ञानिक प्रगति के साथ–साथ सूचना एवं संचार तकनीक के आविर्भाव की यह विकास यात्रा बड़ी तेज, रोचक और रोमांचक रही है। तार टेलीग्राफ से लेकर टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, संचार उपग्रह, इंटरनेट एवं 5 जी जैसी प्रौद्योगिकी ने सूचना–संचार के क्षेत्र को विस्तार देते हुए बड़ा सुगम और सुलभ बना दिया है।

विगत कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण पहलों में अनेक ऑनलाइन सेवाएं – रेलवे टिकट, हवाई टिकट आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण, बैंकों का कम्प्यूटरीकरण एवं एटीएम की सुविधा, इंटरनेट से एफआईआर, न्यायालयों के निर्णय, टेंडर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसी प्रकार किसानों के भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन, काउंसलिंग, परीक्षाएं, आयकर फाइलिंग, कॉन्फिडेंसियल रिपोर्ट, बिजली–पानी, फोन के बिल इत्यादि ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। ये सब ई–गवर्नेंस तथा एम–गवर्नेंस के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रान्ति के उत्तरोत्तर बढ़ते कदमों का प्रमाण है।

पहला कंप्यूटर निदेशालय

सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को व्यवस्थित, योजनाबद्ध तथा उचित दिशा प्रदान करने के लिए 1987 में राज्य में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की गई। 30 सितंबर 1997 को इस का नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया। इसके बाद मई, 2002 में विभाग के कार्यों को देखते हुए इसके नाम को बदल कर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT &C) कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989 में राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज (RSCS) की स्थापना सोसायटी के रूप में की गई थी। संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संचार प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विभिन्न विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना व योजनाओं का क्रियान्वयन करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख कार्य

- राज्य में कंप्यूटरीकरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सभी नीतियों का निरूपण करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट के लिए सुरक्षा नीतियों का निर्माण।
- राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेंस का समन्वय तथा सम्बन्धित योजनाओं का पर्यवेक्षण।
- संपूर्ण राज्य में कॉमर्स तथा इंटरनेट को प्रोत्साहन देना।
- सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना करना।
- साइबर सुरक्षा के उपाय करना।

विभाग के अंतर्गत वर्तमान में दो एजेंसियां कार्यरत हैं –

- राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (RISL)
- राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL)

राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (RISL)

पहले राजकॉम्प और अब आरआईएसएल 2010 में स्थापित राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी परामर्श संगठन है। राजस्थान सरकार के तत्वावधान में यह सॉफ़्टवेयर प्रकाशन, परामर्श, एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर, दस्तावेज़ीकरण, सॉफ़्टवेयर रखरखाव, वेब पेज डिजाइन जैसे कार्यों में संलग्न है।

राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL)

राज्य में व्याप्त डिजिटल डिवाइड को खत्म करने हेतु शहरी तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना की गई है। कंप्यूटर की शिक्षा हेतु RSCIT का कोर्स चलाया जाता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत राज्य कर्मचारियों को कोर्स के शुल्क का पुनर्भरण भी किया जाता है।

ई–गवर्नेंस तथा एम–गवर्नेंस सम्बंधी विभिन्न परियोजनाएं

- **राजस्थान संपर्क –** यह सामान्य लोगों की शिकायतों तथा उनके निवारण के लिए एक एकीकृत मंच है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री के जन सुनवाई कार्यक्रम, मुख्यमंत्री यात्रा तथा अन्य संपर्क माध्यमों का एकीकरण कर दिया गया है। इसी के साथ सीएम हेल्पलाइन का नया नंबर 181 शुरू किया गया है।
- **राज नेट –** इस योजना के माध्यम से पंचायत स्तर तक नेटवर्क का विस्तार कर सभी सरकारी भवनों को जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ 33 जिला मुख्यालयों तथा चयनित ब्लॉक्स में आईपी फोन की सुविधा भी दी गई है। सरकारी कार्यालयों में कई जगह अधिकारियों तथा आगंतुकों के लिए वाइफाइ हॉट स्पॉट की सुविधा दी गई है। प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को बढ़ाकर पंचायत स्तर तक कर दिया गया है। राज्य के लिए एक ही जीआईएस प्लेटफॉर्म तैयार कर राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतों तथा भवनों के 3डी मॉडल तैयार किए जा रहे हैं।
- **ई–मित्र –** राज्य में अब तक 87 हजार से भी अधिक ई–मित्र क्रियाशील कर दिए गए हैं। ई मित्र के माध्यम से राज्य के नागरिकों को 475 से अधिक सरकारी तथा निजी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें बिजली–पानी मोबाइल अधिकृत बिल तथा भामाशाह पासपोर्ट पैन कार्ड सहित विभिन्न प्रमाण पत्र तथा सत्यापन के कार्य भी किए जा रहे हैं।
- **डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र –** राज्य के नागरिकों को सुविधा प्रदान करते हुए अब डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की व्यवस्था की गई है जिसमें घर बैठे ही कियोस्क अथवा एकल खिड़की के माध्यम से नागरिक मूल निवास, जाति तथा आय प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि वैधानिक डिजिटली हस्ताक्षरित होते हैं।
- **स्टेट पोर्टल –** राज्य के समस्त नागरिकों, सरकारी उपयोगकर्ताओं व्यापारियों तथा विदेशी लोगों के लिए सभी सूचनाओं की उपलब्धि हेतु एकीकृत स्टेट पोर्टल बनाया गया है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी विभागों के पोर्टल जुड़े हैं तथा राज्य से सम्बन्धित विभिन्न आंकड़े भी यहां उपलब्ध हैं।
- **ई–संचार एवं आई फेक्ट –** ई–संचार पोर्टल के अंतर्गत किसी भी विभाग की सरकारी योजना की सूचना अथवा नोटिफिकेशन लाभार्थी आवेदनकर्ता तथा सरकारी कर्मचारियों को टेक्स्ट मैसेज या वॉइस कॉल के माध्यम से भेजा जा सकता है। आई फेक्ट का प्रयोग राजस्थान संपर्क के अंतर्गत रियलिटी चैक करने के लिए किया जाता है।

अभिनव प्रयोग एवं नवाचार

- **ई–मित्र प्लस–** इसके माध्यम से सरकार तथा जनता को टेक्नोलॉजी के द्वारा जोड़ने की पहल की गई है। यह कियोस्क वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा देते हैं, जो राज्य के विभिन्न स्थानों को परस्पर जोड़ती है। इस पर नकद डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क भुगतान किया जा सकता है। यह स्वचालित कियोस्क सरकारी स्टेशनरी पर विभिन्न प्रमाण पत्रों यथा जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि को प्रिंट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त लाइव सेशन में सरकारी अधिकारी से जुड़कर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।
- **हिंदी ईमेल –** राजस्थान अपने नागरिकों को हिंदी में ईमेल की सुविधा उपलब्ध कराने वाला कदाचित देश का पहला राज्य है। इसकी शुरुआत डिजीफेस्ट में की गई थी।

- **राज बायोस्कोप –** राज बायोस्कोप राज्य सरकार का वीडियो शेयरिंग पोर्टल है। इस पर इंटरनेट के माध्यम से वीडियो साझा किए जा सकते हैं। पोर्टल सरकार के लिए उपयोगी चैनल के रूप में कार्य करता है जो नागरिकों तथा सरकारी विभागों को सरकार के बारे में जानकारी साझा करने में सहायता प्रदान करता है।
- **सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) आईडी –** राज्य में ई-सेवाओं हेतु सभी विभागों में सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) आईडी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत ई-मित्र संचालकों, वरिष्ठ नागरिकों, निवेशकों तथा राज्य के नागरिकों को यह सुविधा मिल रही है। प्रदेश में अब तक विभिन्न क्षेत्रों में करीब दो करोड़ एसएसओ आईडी बनाई जा चुकी हैं।
- **राज ईवॉलेट –** पेपरलेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नागरिकों को अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए ईवॉलेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। इन दस्तावेजों का ऑनलाइन फार्म भरते समय सीधे उपयोग किया जा सकता है।
- **मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर –** सेंटर की स्थापना मोबाइल एप्लीकेशन के विकास क्रियान्वयन तथा प्रबंधन हेतु की गई है। सेंटर द्वारा विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन डाउनलोड एवं डवलप की जा रही है।
- **डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर –** इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस डेटा को विश्लेषण तथा ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा भविष्य के लिए योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए बिग डाटा तकनीक से लैस एनालिटिक सिस्टम का विकास किया जा रहा है।

- **जन सूचना पोर्टल –** जन सूचना पोर्टल अपनी तरह का पहला प्रयास है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा वार्ड एवं पंचायत स्तर तक क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है।

इसके अलावा ई-गवर्नेंस तथा एम-गवर्नेंस के क्षेत्र में राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (RSDC), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजन (DVAE), राज उद्योग-मित्र पोर्टल, राजस्थान सेंटर फॉर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD), न्यूज मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, (BPAS), राजस्थान स्टार्टअप, वीडियो वाल, राज वीसी, राज वाई-फाई, राजस्वान, राज पेमेंट प्लेटफॉर्म, राज ई-साईन, ई-संचार, राज-काज, राजबोट, रोबोटिक्स, राजसेवा द्वार, ई-बाजार, वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS), आरटीआई पोर्टल, अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, एकीकृत भर्ती पोर्टल, राजधरा, एकीकृत ई-पंचायत सॉफ्टवेयर, राजफेब (RajFab), लाइट्स-न्याय विभाग, राज ई-ज्ञान, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (RAJ-LMS), राजकिसान साथी, सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, चीफ मिनिस्टर इन्फोमेशन सिस्टम, जनकल्याण पोर्टल, ई-लाइब्रेरी, राजकौशल, राजनिवेश एवं ई-बिजनेस पोर्टल जैसे नवाचार राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

जोधपुर में 73वां राज्यस्तरीय वन महोत्सव

पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी जरूरी

अरुण जोशी
अतिरिक्त निदेशक, जनसम्पर्क

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन आज की प्राथमिकता है। इसके लिए हर स्तर पर भागीदारी निभाने के लिए लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया इस बारे में चिन्तित है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों और पर्यावरण चेतना में भागीदारी का संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में वन विभाग की ओर से आयोजित 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने पौधारोपण किया और स्मृति वन में 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बोटेनिकल गार्डन एवं 2 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली लव-कुश वाटिका का शिलान्यास भी किया।

नवीन पर्यटन केन्द्र लेगा मूर्त रूप

इन विकास कार्यों से प्रकृति की गोद में स्थित कैलाश सांखला स्मृति वन देश-दुनिया में अपनी अनूठी पहचान कायम करेगा। पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा और जोधपुर के लिए नवीन पर्यटन स्थल विकसित होगा। इसके विकास में जनभागीदारी से विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के माध्यम से व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्मृति वन में पौधों के संरक्षण के लिए अपील की। इस क्षेत्र की बेरी गंगा से सम्बन्धित समस्याओं का हल वन विभाग ने कर दिया है।

प्रदेश में वन संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में वन विभाग द्वारा संतोषजनक कार्य किए जा रहे हैं। पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में मारवाड़ की अहम भूमिका रही है। खेजड़ली में वृक्षों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान देश-दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक असाधारण एवं ऐतिहासिक घटना थी।

सड़कों के रख-रखाव के लिए स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही फीडबैक के आधार पर सभी प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे। आईटी क्षेत्र के माध्यम से युवाओं को सुनहरा भविष्य प्रदान करने के लिए जोधपुर में फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। चिकित्सा, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं यहां संचालित हैं और अब राजस्थान को देश में मॉडल

स्टेट माना जाता है।

मुख्यमंत्री ने वन विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों, वनौषधियों, वनोपज, हर्बल उत्पादों आदि का अवलोकन किया।

सैटेलाइट अस्पताल डिगाड़ीकलां, जोधपुर के लिए 21.63 करोड़ रुपये स्वीकृत

प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में राज्य सरकार द्वारा अहम फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल डिगाड़ीकलां के भवन निर्माण कार्य के लिए 21 करोड़ 63 लाख 64 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति से अस्पताल के लिए तीन मंजिला भवन निर्माण होगा। यहां सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक, गायनिक के वार्ड (महिला और पुरुष) और आउटडोर, डायग्नोस्टिक लैब के लिए अलग विंग सहित सैटेलाइट अस्पताल के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निर्माण कार्य होंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए बड़े निर्णय लेकर उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत किया जा रहा है। हर अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए प्रदेशवासियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

लम्पी स्किन डिजीज से बचाव एवं रोकथाम हेतु औषधि एवं वैक्सीन खरीद के लिए 30 करोड़ की मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने लम्पी स्किन डिजीज से बचाव तथा रोकथाम के लिए औषधि एवं वैक्सीन खरीदने हेतु 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। राज्य सरकार लम्पी स्किन डिजीज के रोकथाम एवं बचाव के लिए पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले बिना टेंडर के जरूरत की दवाइयां खरीदने जैसे निर्णय लिए जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि पशुपालन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रदेशभर में फैल रही लम्पी स्किन डिजीज से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिलाधिकारियों को औषधि एवं वैक्सीन खरीदने हेतु पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पशुधन में फैल रही लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए वैक्सीन एवं औषधियां आवश्यक मात्रा में तथा कम समय में खरीदी जा सकेंगी और बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा।

क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में मानसून के समय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि स्वायत्त शासन विभाग ने क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए अतिरिक्त राशि प्रावधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से सड़कों के मरम्मत संबंधी कार्य जल्द पूरे होंगे। इससे बारिश में गड्ढों में जल भराव की समस्या कम होगी तथा दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा।

चिरंजीवी योजना से मिल रहा वरिष्ठजन को संबल

राज्य सरकार प्रदेश के वरिष्ठजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता व संवेदनशीलता के साथ फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से हमारे वरिष्ठजन को संबल मिला है और बुढ़ापे में उनको बीमारी के खर्चे से चिंता मुक्त करने का कार्य किया गया है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का गठन करने के साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश के हजारों वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थयात्रा करवाकर उनकी तीर्थयात्रा की मनोकामना को भी राज्य सरकार पूर्ण कर रही है। इसी तरह सदियों से चली आ रही भारत की महान संस्कृति, परंपरा एवं संस्कार के अनुरूप ही राज्य सरकार एक विश्वासपात्र सहारे के रूप में वृद्धजन की सेवा कर रही है।

बीमारी के खर्चे से चिंतामुक्त हुए वरिष्ठजन

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वरिष्ठजन को संबल मिला है और बुढ़ापे में बीमारी के खर्चे से चिंता मुक्त हुए हैं। योजना में

10 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आईपीडी, ओपीडी, जांचें भी निःशुल्क की गई हैं। ट्रांसप्लांट का पूरा खर्च भी सरकार द्वारा ही वहन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपये का बीमा भी किया गया है। प्रदेशवासियों को यह सुविधाएं देने में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है।

पेंशन राशि से बुजुर्गों को संबल

राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें एक करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है, उसमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से संबल मिल सके, इसके लिए प्रदेश में ऐसा कानून बनाया है जिससे बच्चे अपने माता-पिता की सेवा करने के कर्तव्य से विमुख न हों।

फसल नुकसान की भरपाई के लिए 72 घण्टे के भीतर बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत जलभराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। खरीफ-2022 में बीमित फसल को जलभराव के कारण नुकसान होने पर घटना घटने के 72 घण्टे में जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है। किसान फसल में हुई हानि की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस एप के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा सम्बन्धित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। परन्तु किसान द्वारा घटना घटने के 72 घण्टे में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को सूचित किया जाना आवश्यक है।

बारां, धौलपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, झुन्झुंनू, करौली एवं उदयपुर जिले के किसान एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18004196116 पर सूचना दे सकते हैं। इसी प्रकार चूरू, भीलवाड़ा, राजसमन्द, दौसा, झालावाड़, श्रीगंगानगर एवं अलवर जिले के किसान एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18002091111, बांसवाड़ा, नागौर भरतपुर, जयपुर, पाली एवं प्रतापगढ़ के काश्तकार रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18001024088 तथा बूंदी, डूंगरपुर एवं जोधपुर के किसान फ्यूचर जनरल इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के नंबर 18002664141 पर सूचना दे सकते हैं। इसी तरह अजमेर, जालौर, सवाई माधोपुर एवं कोटा के किसान बजाज अलायन्ज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के नंबर 18002095959, जैसलमेर, सीकर एवं टोंक के किसान एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के नंबर 18002660700 तथा बीकानेर, चितौड़गढ़ एवं सिरोही के काश्तकार यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18002005142 पर सूचित कर सकते हैं।

राजस्थान में राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 4 जनवरी 2023 से

- मुख्यमंत्री ने आयोजन के लिए 24.70 करोड़ रुपये की दी स्वीकृति
- पाली जिले के रोहट में होगा आयोजन, हिस्सा लेंगे 35 हजार स्काउट एवं गाइड
- राजस्थान को 66 वर्ष बाद मिली मेजबानी

स्काउट एवं गाइड का सबसे बड़ा कार्यक्रम 'राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी' 4 जनवरी से 10 जनवरी, 2023 तक पाली जिले के रोहट में आयोजित होगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की मेजबानी में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में 1500 विदेशी सहित पूरे देश से 35 हजार से अधिक स्काउट एवं गाइड हिस्सा लेंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जम्बूरी के आयोजन के लिए 24 करोड़ 70 लाख रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को 10 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति दी है।

राजस्थान को 66 साल बाद राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी मिली है। इस 7 दिवसीय जम्बूरी में स्टेट द्वार, पायनियरिंग प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डवलपमेंट, इंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासिलिंग एवं वाटर एक्टिविटीज जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन के लिए बजट वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ रुपये देने के लिए घोषणा की थी।

प्रदेश में 'बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना' लागू

36,300 छात्राओं को होगा शुल्क का पुनर्भरण

मुख्यमंत्री ने पुनर्भरण के लिए दी 14.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस का पुनर्भरण मिलेगा। इससे वे पढ़ाई जारी रखकर भविष्य संवार सकेंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्य में 'बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना' को लागू कर दिया है।

योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल 36 हजार 300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान की है। इसमें ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती हैं, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा।

दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली किशोरियों और महिलाओं के फीस पुनर्भरण हेतु इस योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर के कोर्सेज में 16,000 सीटें, स्नातकोत्तर कोर्सेज में 5300, डिप्लोमा कोर्सेज में 10,000, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में 3000 तथा सर्टिफिकेट कोर्सेज में 2,000 सीटों का प्रावधान किया गया है।

योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान एवं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। उनके द्वारा अध्ययन के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस राशि का पुनर्भरण किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में ही मुख्यमंत्री द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई है।

जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ

स्थायी पीठ के गठन तक चल पीठ की बैठक अवधि हर माह 8 प्रभावी दिवस होगी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी है। साथ ही जोधपुर में स्थायी पीठ का गठन होने तक जोधपुर चल पीठ की बैठक प्रत्येक माह के 8 प्रभावी दिवसों में आयोजित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

इन्वेस्टर्स मीट एंड एमओयू साइनिंग सेरेमनी

- राज्य सरकार और निवेशकों के बीच 69,789 करोड़ रुपये के एमओयू
- जयपुर में 7-8 अक्टूबर, 2022 को आयोजित होगा 'इन्वेस्ट राजस्थान'
- निवेशकों के अनुकूल उपलब्ध नीतिगत ढांचे से राजस्थान बना निवेशकों का पसंदीदा राज्य
- निवेशक राज्य में औद्योगिक विकास के लिए दें सकेंगे सुझाव

राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना को लेकर अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इससे निवेशकों को राज्य में निवेश करने में आसानी हुई है। यहां निवेशकों की समस्याओं को सुनना और प्रतिबद्धता के साथ उनका समयबद्ध निस्तारण करना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। वर्तमान में रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, सौर ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा विकास आदि में भारी निवेश करने वाले राज्य के रूप में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान निवेशकों के लिए उपलब्ध अनुकूल नीतिगत ढांचे से पहली पसंद बना है।

रीको द्वारा राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। एनसीआर का 25 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में होने से देशभर से प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी है। कानून-व्यवस्था, बेहतरीन सड़कें तथा अनुकूल परिस्थितियों के साथ निवेश करने के लिए राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। इससे निवेशकों को बड़ा फायदा मिलेगा।

अब तक करीब 11 लाख करोड़ के एमओयू एवं एलओआई हो चुके हैं। राजस्थान में सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता के साथ-

साथ अब निवेशकों की भी विविधता है। रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रोप्रोसेसिंग, माइनिंग, ई-व्हीकल, सेरेमिक तथा ग्लास के क्षेत्र में निवेश इसके प्रमाण हैं।

रिप्स के तहत निवेशकों को उनकी जरूरत के अनुसार पैकेज दिए जा रहे हैं। एमएसएमई-2019 के तहत नवीन उद्यम इकाइयों को 3 साल तक किसी सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होने के साथ वन स्टॉप शॉप प्रणाली से सभी सरकारी स्वीकृतियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा सौर व पवन ऊर्जा, एमएसएमई एवं रिप्स सहित विभिन्न सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाई गई है।

जोधपुर जिले में 14 हजार एकड़ में फैला विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। जैसलमेर में सिर्फ 2 मेगावाट विंड एनर्जी थी, वर्तमान में 5000 मेगावाट एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सभी निवेशकों से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं।

डीएफसी कॉरिडोर एरिया का 40 प्रतिशत और डीएमआईसी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा राज्य से गुजरता है। सबसे बड़े राज्य और स्ट्रेटेजिक स्थिति के चलते राजस्थान निवेश की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में वन स्टॉप शॉप, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

निवेश के लिए राजस्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान बन गया है। राजस्थान को अब अवसरों की भूमि कहा जाता है। राजस्थान में एक ही पोर्टल पर निवेशकों को विभिन्न अनुमोदन प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार जयपुर में नए कार्गो कॉम्प्लेक्स, एक्सपोर्ट क्लियरेन्स के लिए नवीन फैसिलिटी और उदयपुर में नए कार्गो कॉम्प्लेक्स, बीकानेर में आईसीडी के साथ राजस्थान के विकास की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

69,789 करोड़ रुपये के एमओयू

नई दिल्ली में राज्य सरकार और निवेशकों के बीच 69,789.93 रुपये के एमओयू हुए। इससे राज्य में कुल 11846 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इनमें अवड्डा पावर द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट पर लगभग 40,000 करोड़ रुपये, ओ2 पावर एसजी पीटीई द्वारा अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा सेक्टर में 25,000 करोड़ रुपये, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड द्वारा 1400 करोड़ रुपये, सेंट गोबेन द्वारा 1000 करोड़ रुपये के निवेश से फ्लोट ग्लास मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के प्रस्ताव हैं। वरुण बेवरेजेज लिमिटेड द्वारा 636 करोड़ रुपये की कार्बोनेटेड सॉफ्ट-ड्रिंक्स, फ्रूट-जूस एवं पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जायेगी। विप्रो जयपुर में हाइड्रोलिक सिलेंडर प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

राज्य भर के थियेटर्स में हुआ 'गांधी' फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन–

आजादी के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य भर के थियेटरों में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित ऑस्कर विनर फिल्म 'गांधी' का निःशुल्क प्रदर्शन हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को समर्पित इस फिल्म को राज्य के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में देखा और महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों और उनके सिद्धांतों से परिचित हुए। मार्निंग शो में फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन 1 सितम्बर तक हुआ।

सूचना एवं जनसम्पर्क, कला एवं संस्कृति तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने फिल्म के प्रदर्शन के लिए सरकार के निर्णय के बाद नेशनल फिल्म डिवीजन कॉरपोरेशन से विशेष अनुमति ली थी। जिलों में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

गांधी फिल्म के निःशुल्क प्रदर्शन के पीछे सरकार का उद्देश्य गांधी दर्शन तथा मानव मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को जाग्रत करना है। जिस तरह से महात्मा गांधी की प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी बरकरार है, उसी प्रकार यह फिल्म आज के दौर में प्रासंगिक है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1982 में आयी 'गांधी' फिल्म को ऑस्कर के लिए 11 कैटेगिरी में नामित किया गया था, जिसमें फिल्म ने 8 श्रेणियों में ऑस्कर अवार्ड जीता था। 3 घंटे 11 मिनट की इस फिल्म में 'बेन किंग्सले' ने महात्मा गांधी की अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी तथा रोहिणी हटंगड़ी ने अपने अभिनय से कस्तूरबा गांधी की भूमिका को अमर कर दिया था।

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। करौली में हवाई सर्वेक्षण

- कोटा, बूंदी, बारां, धौलपुर के बाद करौली का हवाई सर्वेक्षण
- तीन दिन में पांच जिलों का दौरा कर बाढ़ प्रभावितों से मिले

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने करौली जिले के मंडरायल एवं करणपुर क्षेत्र के करई, बबूल खेड़ा, बंधवारा, झूकरी, मल्हापुरा, फतेहपुरा, दर्रा, नींदरपुरा एवं गोटा सहित अन्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों और कोटा बैराज एवं अन्य बांधों से छोड़ गए पानी से प्रभावित गांवों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए प्रभावितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने मंडरायल पहुंचकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावितों के लिए बनाए गए अस्थाई आवास, भोजन, पेयजल, चिकित्सा, विद्युत, सफाई आदि का विशेष ध्यान रखा जाए। प्राकृतिक आपदा के कारण आमजन को घर, मवेशी, कृषि सहित अन्य प्रकार का जो भी नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करवाकर त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। श्री गहलोत ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। आत्मीयता से उनकी समस्याएं सुनी एवं उचित मुआवजा दिलाने का विश्वास दिलाया।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए आमजन को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। चिकित्सा सम्बन्धित योजनाओं से आमजन को संबल मिला है।

प्रदेश के सीमावर्ती जिलों का विशेष रूप से ध्यान रखकर विकास किया जा रहा हैं। प्रदेश के प्रत्येक उपखंड क्षेत्र में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बनाये जा रहे हैं, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक रहकर लाभ उठायें और अन्य लोगों को भी जागरूक करें।

मंत्रिमंडल में युवाओं, कार्मिकों, उद्यमियों के हितों पर अहम निर्णय

सार्वजनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और जनसंतुष्टि के लिए अथॉरिटी का गठन

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के युवाओं के हितों में अनेक अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें जहां ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा छूट के प्रावधानों में 4 सेवा नियमों को जोड़कर राजकीय नियुक्तियों के रास्ते खोले गए हैं। वहीं, पंचायती राज एलडीसी भर्ती-2013 के 4000 पदों को भरने की कार्यवाही आगे बढ़ाकर और शिथिलन देकर राजकीय नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं को सौगात दी है।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफार्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन, शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के नवीन नियुक्ति नियम जारी करने, राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 जारी करने, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को ओ एंड एम मॉडल के अंतर्गत संचालित करने, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग को कंपनी अधिनियम में स्थापित करने, भरतपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्व. श्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर करने तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

राजस्थान सोशल एण्ड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का होगा गठन

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जनसहभागिता, जनसंतुष्टि व गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। राजकीय विभागों तथा उपक्रमों व योजनाओं, कार्यक्रमों को लागू करने वाली अन्य एजेंसीज के कार्य निष्पादन का आंकलन भी हो सकेगा। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभार्थियों तक और अधिक सहजता, सुगमता व समयबद्ध तरीके से पहुंचेगा। अथॉरिटी में चिकित्सक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सांख्यिकीविद्, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, सूचना तकनीक विशेषज्ञ, कर विशेषज्ञ, पीएफएम विशेषज्ञ व अन्य विभिन्न डोमेन के विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार रखा जाएगा।

राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 जारी

परम्परागत हस्तशिल्प को मिलेगा बढ़ावा

मंत्रिमंडल ने ''राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022'' का अनुमोदन कर दिया है। इससे हस्तशिल्पियों के उत्थान में कार्य किए जाएंगे। उन्हें सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

हस्तशिल्प की ब्रांड बिल्डिंग, ई-मार्केटिंग के लिए सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ऋण की सुविधा, छात्रवृत्ति, मेलों में हिस्सा लेने पर सहायता, क्राफ्ट विलेज में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, हैंडीक्राफ्ट पार्क, म्यूजियम, डिजाइन सेंटर, विक्रय केंद्र के लिए सहायता, डिजाइन बैंक स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे। इसके राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, राजस्थान होंगे।

शहीद के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति में राहत

नवासा/नवासी, भाई, बहन, उनके पुत्र व पुत्री भी आश्रित श्रेणी में

मंत्रिमंडल ने राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों में अहम संशोधन कर राहत प्रदान की है। राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2018 को निरस्त कर नये नियम 'राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2022' को स्वीकृति दी गई है।

अभी तक 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है। इसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक की अवधि कर दी गई है। इससे 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी लाभ मिल सकेगा। वहीं, अब कुटुम्ब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, पुत्री/दत्तक पुत्री, पौत्र/दत्तक पौत्र, पौत्री/दत्तक पौत्री के साथ-साथ नवासा/दत्तक नवासा, नवासी/दत्तक नवासी को और शहीद अविवाहित होने पर भाई या बहन, भाई का पुत्र/पुत्री, बहन का पुत्र/पुत्री को भी आश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है।

साथ ही अब राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1966 के अनुरूप ही शहीद आश्रितों को भी उक्त नियमों में अधीनस्थ सेवाओं/मंत्रालयिक सेवाओं एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवा के सीधी भर्ती के पे-लेवल 1 से 10 तक के पदों पर नियुक्ति मिल सकेगी।

पंचायतीराज कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती-2013 में भरे जाएंगे 4000 पद

मंत्रिमंडल ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 के क्रम में 4000 अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देने का बड़ा निर्णय लिया है। जिला परिषदों द्वारा राजस्थान पंचायती राज के प्रावधानों के अनुसार भर्ती आयोजित की गई थी। वर्ष 2017 में बंद भर्ती प्रक्रिया को अब फिर से शुरू किया जा रहा है। अब 2013 की वरीयता सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। पदों को भरने की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने एवं वांछित शिथिलन के प्रस्ताव का अनुमोदन बैठक में किया गया है।

ईडब्ल्यूएस को राहत, शेष 4 सेवा नियमों में भी अधिकतम आयु में छूट

मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। आवेदन की अधिकतम आयु सीमा छूट में शेष रहे 4 सेवा नियमों को भी शामिल करने पर मोहर लगाई गई है।

अब 'राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम एवं राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम में भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इससे निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को आयु सीमा में लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसमें ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।

अन्य राज्य या केन्द्र सरकार में कार्यरत पदक विजेता कार्मिकों को मिलेगा राज्य में पे-प्रोटेक्शन

मंत्रिमंडल ने 'राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017' में संशोधन किया है। इससे राजस्थान राज्य के निवासी जो किसी अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार में अधिकारी/कर्मचारी है, उन्हें खेलों में पदक जीतने पर राज्य में पे-प्रोटेक्शन मिलेगा।

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग

मंत्रिमंडल ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से प्रदेश में उद्योग स्थापना की सम्भावनाओं में बढ़ोतरी होगी। राज्य में उन्नत तकनीक युक्त युवा शक्ति उपलब्ध होगी।

इंस्टीट्यूट से युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप को नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एवं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्रों में पढ़ने एवं अनुसंधान करने का मौका मिलेगा। इंस्टीट्यूट उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में परामर्शदात्री के रूप में कार्य करेगा।

प्रदेश के 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थापित होगी फिंगरप्रिंट लैब

- मुख्यमंत्री ने कुल 23 करोड़ 40 लाख रुपये की दी मंजूरी
- जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में होगी लैब स्थापित
- प्रत्येक प्रयोगशाला पर होगा 5 करोड़ 85 लाख रुपये का व्यय
- आपराधिक प्रकरणों के सटीक एवं त्वरित अनुसंधान में मिलेगी सहायता

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना के लिए 23 करोड़ 40 लाख रुपये (प्रत्येक के लिए 5.85 करोड़) की राशि को स्वीकृति दी है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में डीएनए फिंगरप्रिंट सुविधाओं का विस्तार करने की घोषणा की थी। उक्त राशि से महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब के निर्माण के लिए सिविल वर्क, लैब के संचालन के लिए विभिन्न उपकरण, फर्नीचर, कैमिकल एवं कन्ज्यूमेबल आइटम की खरीद तथा आवश्यक विभिन्न संवर्गों के पदों का सृजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से राज्य में आपराधिक प्रकरणों के सटीक, प्रभावी तथा त्वरित अनुसंधान में सहायता मिलेगी तथा पीड़ितों को कम समय में न्याय मिल सकेगा।

फूड ट्रेल बस

- बस में देश के जाने-माने सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स एवं फूड ब्लॉगर्स की राजस्थान यात्रा
- प्रदेश की संस्कृति और खान-पान का प्रचार

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 'टाइम्स पैशन फूड ट्रेल' कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉगर्स एवं सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स की बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। पर्यटन विभाग और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस यात्रा में देश के लगभग 30 प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स एवं फूड ब्लॉगर्स एक बस में राजस्थान के विभिन्न शहरों की यात्रा करेंगे तथा प्रदेश के खान-पान एवं व्यंजनों के बारे में सोशल मीडिया पर प्रचार करेंगे।

पैशन फूड ट्रेल का यह प्रयोग अपने आप में अनूठा है। फूड ब्लॉगर्स एवं सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स का समाज में अपना प्रभाव है। इस यात्रा के माध्यम से वे राजस्थान के अलग-अलग जिलों के खान-पान एवं विशिष्ट व्यंजनों के बारे में जान पाएंगे तथा सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान की पाक-कला का देश-विदेश में प्रचार कर पाएंगे। इस अभिनव पहल से राजस्थान की संस्कृति और विविधता भरे खान-पान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी तथा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं तथा प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को पहली बार उद्योग का दर्जा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि राज्य में इस वर्ष घरेलू पर्यटकों की संख्या में 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

3,324 करोड़ के सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण

- 3063 किमी लंबाई की 113 सड़कों, आरओबी एवं पुलों का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण
- सड़क निर्माण में गुणवत्ता से नहीं होगा कोई समझौता
- निवेश एवं विकास के लिए अच्छी सड़कें जरूरी
- सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
- मानसून में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत
- राजस्थान की सड़कें गुजरात से बेहतर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 3324 करोड़ रुपये की लागत की 3063 किमी लंबाई की सड़कों, आरओबी तथा पुलों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। सड़कों का विकास नागरिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जहां सड़कों का विकास होगा वहां नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना होगी। राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

गुणवत्ता से नहीं किया जाएगा कोई समझौता

सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की

प्राथमिकता है। इसके लिए निरीक्षण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा तथा गुणवत्ता नियंत्रण शाखा के अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने तथा उचित मापदण्डों के अनुसार सड़कों का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभागीय अधिकारी ठेकेदारों से समन्वय कर सड़क बनने के बाद आवश्यक रखरखाव सुनिश्चित करें। इसके लिए ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंध में मौजूद सभी शर्तों की पालना आवश्यक रूप से करवाई जाए। साथ ही, अधिकारी नियमित एवं औचक दौरे कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

विकास एवं निवेश के लिए उत्कृष्ट सड़क तंत्र आवश्यक

किसी भी राज्य में निवेश एवं विकास के लिए उत्कृष्ट सड़क तंत्र पहली शर्त होती है। सभी विकसित देशों की प्रगति के पीछे उनकी उन्नत सड़कें एक मुख्य कारण हैं। राज्य में अक्टूबर में होने जा रही इन्वेस्ट राजस्थान समिट से पहले प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों के साथ लगभग 11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन कर लिए गए हैं। निवेशकों द्वारा प्रदेश में दिखाई जा रही रुचि के पीछे राज्य का सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर एक प्रमुख वजह है। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण मुख्य जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर विकास में राज्य के सभी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

क्षतिग्रस्त सड़कों की हो तुरंत मरम्मत

प्रदेश में इस बार सभी जिलों में अच्छी बरसात हुई है तथा कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हुई है। मानसून में हुई अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण सड़कों को व्यापक नुकसान भी हुआ है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को 20 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। सभी जिलों में सड़कों की मरम्मत के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा संसाधनों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंधों की पालना करवाते हुए दोष निवारण अवधि के दौरान सड़कों हुई किसी भी प्रकार की टूट-फूट की त्वरित मरम्मत हेतु उन्हें पाबंद किया जाए।

राज्य में लगातार सड़कों का निर्माण और विकास हो रहा है। गत साढ़े 3 वर्षों में राज्य में 42,384 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों के विकास के लिए 25,395 करोड़ रुपये की लागत से 10,546 विकास कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। यह सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज राज्य की सड़कें गुणवत्ता की दृष्टि से पड़ोसी राज्य गुजरात से बेहतर स्थिति में हैं।

सड़कों को चिरस्थायी बनाने के लिए हो रहा नई तकनीकों का उपयोग

सड़कों की ज्यादा आयु एवं बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 'कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी' के माध्यम से क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र तथा टिकाऊ मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़कों की उपयोग योग्य सामग्री का इस्तेमाल नई सड़कों में किया जा रहा है। सेल फिल्ड जैसी तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता की सीमेंटेड सड़कें बनाई जा रही हैं। साथ ही, अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग भी सड़क निर्माण में किया जा रहा है।

गौरवशाली विरासत है: गागरोन का जलदुर्ग

राजस्थान की न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में उसके समृद्ध इतिहास और महान ऐतिहासिक धरोहरों की वजह से एक खास पहचान है। विविधता, सौंदर्य और संस्कृति को खुद में समेटे राजस्थान के हर जिले की अपनी खासियत है। झालावाड़ जिला भी अपनी एक विशेष पहचान रखता है। यहां के प्राचीन मन्दिर, मौसम, वृक्षों से हरे-भरे पर्यावरण के साथ ही यहां स्थित गागरोन का किला इस जिले की खास पहचान है।

अनुप्रिया
जनसंपर्क अधिकारी

झालावाड़ का गौरव है गागरोन का किला

गागरोन का किला पूर्वी राजस्थान में स्थित कई दुर्गम और मजबूत किलों में से एक है। यह किला कालीसिंध और आहू नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। तीन ओर से नदियों से घिरा होने की वजह से इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। इस तरह के दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत और अभेद्य होते थे।

गीध कराई पहाड़ी

गागरोन किले के पार्श्व में कालीसिंध के तट पर एक ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी को गीध कराई पहाड़ी कहते हैं।

गागरोन किले में विशिष्ट स्थल

तिहरे परकोटे से सुरक्षित गागरोन दुर्ग के प्रवेश द्वारों में सूरजपोल, भैरवपोल तथा गणेशपोल प्रमुख हैं। इसकी सुदृढ बुर्जों में राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज है। यहां राजा-रानियों के महल, विशाल कुण्ड, बारूदखाना, नक्कारखाना, टकसाल, मंदिर, दरगाह तथा बुलन्द दरवाजा प्रमुख है।

स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं में अग्रणी: राजस्थान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रदेशवासियों को सुशासन देने हेतु राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से विभिन्न योजनाओं व सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ आमजन को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान एक अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार 10 लाख तक के सालाना बीमा का प्रावधान है। कॉकलियर इम्पलांट, बोन कैंसर जैसी बीमारियों के भी नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सारा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी इस योजना में शामिल है।

स्वास्थ्य सेवा मुख्यमंत्री की प्राथमिकता रही है। निरोगी राजस्थान के विजन के साथ आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पब्लिक हैल्थ सेन्टर खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में सेटेलाईट चिकित्सालयों में 40 विशिष्ट जांचें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 20 लाख मरीजों की 1.36 करोड़ विशिष्ट जांचे की जा चुकी हैं। 18 लाख से अधिक मरीजों के इलाज पर लगभग 2203 करोड़ रुपये की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आउटडोर व इनडोर सुविधायें नि:शुल्क की गई है। प्रदेश में

डॉ. सत्यनारायण सिंह
आई.ए.एस.(आर.)

2 नये सीएचसी, 338 पीएचसी व 215 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले गये हैं। 39 उपजिला अस्पताल, 21 जिला चिकित्सालयों में 8 को सेटेलाइट अस्पताल और 194 को सीएचसी में अपग्रेड किया गया है। प्रदेश में ट्रोमा सेंटर्स की स्थापना के साथ विभिन्न अस्पतालों में 8,416 सेंटर्स की स्थापना के साथ विभिन्न अस्पतालों में 8,416 बेड्स बढ़ाये गये हैं। आयुष्मान योजना के तहत 8,394 उपस्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों में परिवर्तित किया गया है। 3,613 दवा वितरण केन्द्रों का निर्माण किया गया है। 8 जिलों में नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं, 7 जिलों में नवीन कॉलेजों की स्थापना की जा रही है।

स्वास्थ्य सेवा मुख्यमंत्री की प्राथमिकता रही है। निरोगी राजस्थान के विजन के साथ आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पब्लिक हैल्थ सेन्टर खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में सेटेलाइट चिकित्सालयों में 40 विशिष्ट जांचें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 20 लाख मरीजों की 1.36 करोड़ विशिष्ट जाचें की जा चुकी हैं।

प्रति कॉलेज 44 पदों के अनुसार 838 नये पदों का सृजन किया गया है। 352 उपजिला चिकित्सालयों में डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 142 जनता क्लीनिक कच्ची बस्तियों और अल्प आय वर्ग के मोहल्लों में खोले जाएंगे। जयपुर में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर व सुविधाओं के क्षेत्र में विश्वस्तरीय किया जा रहा है। आईपीडी टावर व हृदय रोग संस्थान निर्माण, रोबोटिक सर्जरी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। महिला चिकित्सालयों में कैंसर संस्थान का विकास प्रारम्भ हो गया है। चार बड़े शहरों में मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रारम्भ किये जा रहे हैं। कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम लागू किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 10.52 लाख बच्चों का इलाज कराया गया है जिसमें 8,000 से अधिक बच्चों की जनरल हार्ट सर्जरी हुई है।

राज्य के बेहतरीन कोराना प्रबन्धन की देश विदेश में सराहना हुई है। 32 लाख निराश्रित परिवारों को 5,500 रुपये की सहायता दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। 210 नये राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं जिनमें 94 कन्या महाविद्यालय है। प्रदेश में 1206 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं ताकि वंचित तबके के विद्यार्थी भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सरकार ने 90 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम से जोड़ने का काम किया। पालनहार योजना में 6.05 लाख बच्चों को 1719.41 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। बेघर लोगों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लाई, घुमन्तु समुदायों के उत्थान के लिए डीनोटीफाइड ट्राइब्स पॉलिसी लाई जा रही है।

राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ आमजन को पंहुचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। 5 वर्ष तक किसानों के लिए बिजली दरों में वृद्धि नहीं होगी, प्रतिमाह 1000 रुपये बिजली बिल अनुदान, 21 लाख किसानों को 15,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ, 18,000 करोड़ रुपये का अनुदान, इंदिरा महिला सशक्तीकरण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की निधि। समस्त किशोरियों और महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकीन वितरण, प्रशासन शहरों के संग, शहरों की अवैध रूप से बनी बस्तियों को पट्टों का वितरण एवं राज्य के करीब 5 लाख कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया। अपराध रोकने के लिए थानों व पुलिस को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा पुलिस थानों में निर्बाध पंजीयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना एक महत्त्वाकांक्षी योजना बन गई है। कोरोना काल में इस योजना के माध्यम से लाखों श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर रही है, इस योजना की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार

राज्य के बेहतरीन कोराना प्रबन्धन की देश विदेश में सराहना हुई है। 32 लाख निराश्रित परिवारों को 5500 रुपये की सहायता दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। 210 नये राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं जिनमें 94 कन्या महाविद्यालय हैं। प्रदेश में 1206 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं ताकि वंचित तबके के विद्यार्थी भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

गारंटी योजना शुरू की गई है। इंदिरा गांधी कम मूल्य भोजन योजना व श्रमिकों का जीवन सुधार हेतु नई सिलिकोसिस नीति लागू की गई। कार्यस्थल पर बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए खान मालिकों को पाबन्द किया गया है। पीड़ितों को आर्थिक सहायता के साथ मृत्यु पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित की गई है। 10 करोड़ रुपये के प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना एवं विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत हजारों लोगों को लाभान्वित किया।

महात्मा गांधी शांति एवं अहिंसा निदेशालय को एक विभाग के रूप में स्थापित किया जा रहा है। समस्त सरकारी विभागों में पुराने व नवीन सृजित पदों पर नौकरियां दी जा रही हैं। अब तक लाखों युवकों को नौकरी दी जा चुकी है। कर्मचारियों और पेंशन परिवारों को सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस की कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है।

स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए नई सोच व नई दिशा अपनाते हुए अहम कदम उठाये हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा साढे चार सौ से अधिक ट्रेप प्रकरण दर्ज किये गये हैं। लोक सेवकों के बारे में सूचना का प्रभावी संकलन व विश्लेषण किया जा रहा है। सूचना के अधिकार कानून की पालना सुनिश्चित की जा रही है। आमजन के सभी जायज काम समय पर निष्पादित हों तथा उन कार्यो के निष्पादन में भ्रष्टाचार रुकावट नहीं बन सके इसके लिए अधिकाधिक जन सुनवाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साम्प्रदायिक ताकतों ने प्रदेश के कई जिलों में तनाव व अशांति पैदा करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार की घटनाओं को शीघ्रता से कार्रवाई कर व आवश्यक कदम उठाकर रोका गया है। अन्य घटनाएं नहीं हों इसके लिए प्रशासन व पुलिस को पूरी तरह सतर्क किया हैं सभी धार्मिक आस्थाओं के प्रति एक जैसा सम्मान प्रदर्शन कर सामाजिक व धार्मिक सद्भाव सुनिश्चित किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

शिवचन्द मीणा
संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क

प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार के अवसर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितम्बर को शुरू की है। प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर परिवार खुशहाल हो इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर राज्य में 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' लागू करने की अभिनव पहल राज्य सरकार द्वारा की गई है।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के वंचित, गरीब एवं बेरोजगार बच्चों को बड़ा संबल दे रही है। हर हाथ को रोजगार के उद्देश्य के साथ शुरू हुई इस योजना में मात्र 6 दिन में ही प्रदेश के विभिन्न शहरी क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

शहरों में बसे जरूरतमंद तबके में इस योजना के प्रति खासा उत्साह एवं आकर्षण है। स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार योजना के तहत अब तक 2 लाख 45 हजार से अधिक परिवारों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इन परिवारों के 3,83,639 लोगों के नाम जॉब कार्ड में शामिल हैं। अब तक 96 हजार 452 परिवारों के 1,39,798 लोगों ने रोजगार की मांग की है, जिनमें से पहले 6 दिवस में ही लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है।

इस योजना में मांग के अनुरूप तुरंत प्रभाव से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति आजीविका के लिए रोजगार से वंचित नहीं रहे। योजना में अकुशल श्रमिक की मजदूरी 259 रुपये प्रति दिवस, मेट का मानदेय 271 रुपये एवं कुशल श्रमिक की मजदूरी 283 रुपये प्रति दिवस निर्धारित की गई है। रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित अवधि में उनके बैंक खातों में होगा।

महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

बेरोज़गारी पर निरन्तर प्रहार

अब
राजस्थान
के शहरों में भी
रोजगार की गारंटी

"कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए यूपीए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने सम्बल प्रदान किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना नहीं है। अतः राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवनयापन करने में मदद मिलेगी।"
अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

इंदिरा गांधी
शहरी रोजगार गारंटी योजना

प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में 9 सितंबर 2022 से शुभारंभ

इच्छुक परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार

आज ही अपने नगरीय निकाय या किसी भी ई मित्र केंद्र पर पंजीकरण कराएं

जन आधार कार्ड के माध्यम से अपने परिवार का पंजीकरण करवाएं

18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के लोग पात्र

अब तक 2 .25लाख से अधिक परिवारों द्वारा पंजीकरण

योजना के तहत करवाए जाने वाले कार्य

- पर्यावरण संरक्षण • जल संरक्षण
- हेरिटेज संरक्षण • उद्यानों का रखरखाव
- अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाना
- स्वच्छता एवं सेनिटेशन एवं अन्य कार्य

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://irgyurban.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

जर्रे–जर्रे से बना आशियाना – अबाबील की वास्तु इन्जिनियरिंग

लक्ष्मण पारंगी
छायाकार एवं स्वतंत्र पत्रकार

इण्डियन क्लिफ स्वलोज ने अपनी कॉलोनी की मरम्मत करने व मिट्टी से घोंसले बनाने का कार्य शुरु कर दिया है। बारिश आते ही किसी सुनसान चट्टानों के बीच सुरक्षित स्थान पर अपनी चोंच में ताजी, साफ सुथरी गीली कीचड़ मिट्टी भर कर जर्रे–जर्रे से अपने आशियानों को एक जैसा आकार दिया जाता है। बारिश के बाद पनपने वाले साफ कीचड़ को काम में लिया जाता है। इनके घोंसलों वाली कॉलोनियां मधुमक्खियों के छत्तों के कोठरों जैसी ही होती है। जिसके मुंह पर पाइपनुमा प्रवेशद्वार होता है। ये जुलाई से दिसम्बर व अप्रेल में भी घोंसले बनाते हैं। इनके घोंसले नदियों व बडे जल भराव वाली जगहों में पाये जाते है। ये चिड़ियां पानी के आस पास उड़ने वाले कीट–पतंगों को खाते हैं। इनके घोंसले बड़े समूहों वाले जिनमें कम से कम 100 से 150 घोंसले एक समूह में होते हैं।

ये हल्के भूरे व सफेद तीन से चार अण्डे देते हैं। इन्हें ''स्टीकथ्रोटेड स्वालों'' व ''नहर अबाबील'' के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान में इन्हें ''हिरन्डू फ्लूवाईकोला'' के नाम से पहचाना जाता है। इन चिड़ियाओं के सामूहिक घोसलें कई सालों तक बने रहते है। बारिश के बाद जिस कीचड़ से ये घासलें बनाते है उसमें इनकी लार के कारण ये मिट्टी चट्टानों पर भी मजबूती से चिपक जाती है जो कई सालों के बाद भी अपने आप नहीं बिखरती। ये घोंसले पीढ़ी दर पीढ़ी पुस्तैनी घर जैसे होते हैं, जिनमें लगातार परिवार अनवरत चलते रहते है।

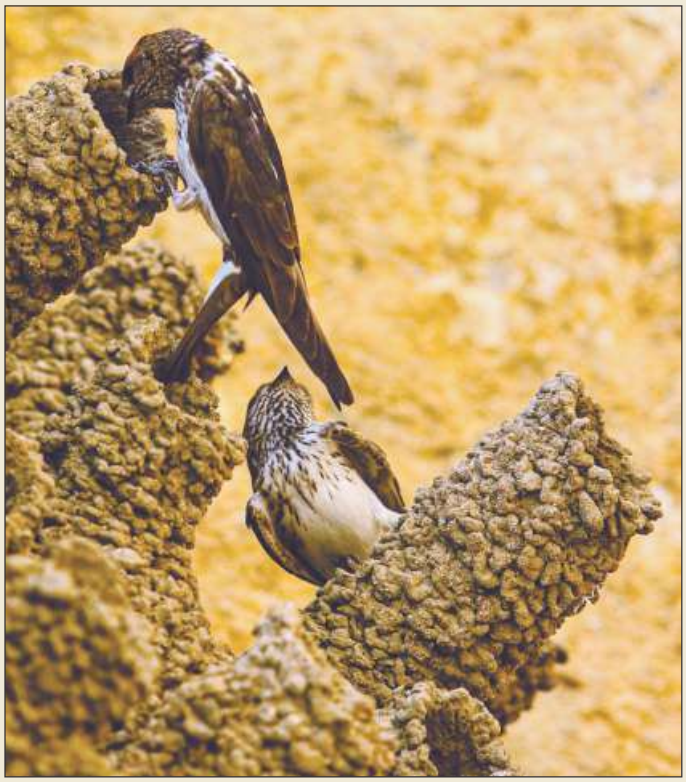

ये भी बनाते हैं मिट्टी के घोसलें

डस्की क्रेग मारटिन, स्वालो, निलगिरी हाउस स्वालो, इण्डियन क्लिफ स्वालो, वायरटेल स्वालो, रेड रम्प्ड स्वालो व हाउस मारटिन भी मिट्टी से अपने घोंसले बनाते हैं। इनमें कुछ समूहों में तो कुछ एकान्त में घोंसले बनाये जाते हैं। इनमें कुछ कटोरे के आकार के और कुछ विचित्र प्रकार के घोसलें होते हैं।

प्रकाश एक अभियान

आओ पढ़ें–पढ़ाएं और बच्चों को आगे बढ़ाएं

धीरज कुमार दवे
जनसंपर्क अधिकारी, नागौर

शिक्षा वह दीपक है जिसके घर में एक बार जलने से न जाने कितनी ही पीढ़ियां रोशन होती रहती हैं। इसी सोच के साथ नागौर में गरीब, झुग्गी झोपड़ियों वे कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवारों के शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोडने के उद्देश्य से अभिनव पहल करते हुए जिले में ''प्रकाश एक अभियान–सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर–पढ़े पढ़ाए, बच्चों को आगे बढ़ाएं'' की शुरुआत की है। जिला प्रशासन एवं बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्त्वावधान में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत किसी कारणवश शिक्षा से वंचित व विकास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

नागौर जिले में रह रहे ऐसे परिवार जो शिक्षा व स्वास्थ्य सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। उन परिवारों के बच्चों के शिक्षा पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन एवं बाल कल्याण समिति द्वारा ''प्रकाश–एक अभियान'' का आगाज किया गया है। इस अभियान के द्वारा बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल रहा है एवं बच्चों के परिवारों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

बच्चों का चिह्नरिण

बच्चों के चिह्नीकरण को लेकर सर्वे टीम का गठन किया गया है जिसमें स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग,महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, स्थानीय स्तर पर थाना पुलिस व बाल कल्याण अधिकारी शामिल हैं। जो स्थानीय बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल, प्रमुख चौराहे व कच्ची बस्तियों आदि का सर्वे कर बच्चों का डाटा संकलन कर रहे हैं।

दस्तावेजीकरण

सर्वे टीम द्वारा किए गए सर्वे एवं डाटा संकलन के आधार पर सर्वे के बच्चों के दस्तावेजीकरण का कार्य किया जाता है, जिसमें कर बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्रों को बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

विद्यालयों में प्रवेश

बच्चों की पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजीकरण के पश्चात स्थानीय प्रशासन शिक्षा विभाग के साथ मिलकर शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं जिसमें ड्रॉप आउट बच्चे भी शामिल हैं।

मूलभूत आवासीय सुविधाओं पर कार्य योजना

वे बालक बालिकाएं जिनके पास आवास नहीं है या घूमंतु परिवारों से हैं तो उन बच्चों के राजकीय छात्रावास में आवास को लेकर प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सम्बन्धित उपखंड अधिकारी क्षेत्र के एनजीओ व भामाशाहों से संपर्क करके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए आवश्यक सुविधाएं यथा यूनिफॉर्म, शू, बैग, नोट बुक व स्टेशनरी भी उपलब्ध करवा रहे हैं।

सम्बन्धित उपखंड के उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में ''प्रकाश एक अभियान'' संचालित किया जा रहा है एवं प्रत्येक सोमवार को ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक में इस अभियान की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, विकास अधिकारी या प्रतिनिधि शामिल हैं।

इस अभियान के तहत सितंबर के पहले सप्ताह तक जिले में शिक्षा से वंचित लगभग 500 बच्चों को शिक्षा से जोडा जा चुका है। जिसमें हाल ही में जिला कलक्टर की मौजूदगी में नागौर शहर में विद्यालय में प्रवेशित हुए 50 बच्चे भी शामिल हैं। इन बच्चों को श्री देव जसनाथ ट्रस्ट पांचला सिद्ध आसन के महंत योगेश्वर सूरज नाथ सिद्ध द्वारा निःशुल्क विद्यालय गणवेश, बैग, जूते, पानी की बोतल वितरित किये गए। वहीं हाल ही में रियांबडी उपखंड में ग्राम जसनगर, भेरूंदा व रियांबडी के झोपड़ियों में निवासरत 20 बच्चों को भी विद्यालय में प्रवेश करवाया गया।

उल्लेखनीय है कि वे बच्चे जो विद्यालय से ड्रॉप आउट हो गए हैं या पारिवारिक अथवा विशेष कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी पुनर्वास की प्रक्रिया को लेकर शुरू किये गए इस अभियान का जिला कलक्टर व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने पोस्टर के विमोचन के साथ आगाज किया था।

महिला सशक्तीकरण के लिए मील का पत्थर: 'महिला निधि'

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिला समानता दिवस पर जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर में महिला स्वयं सहायता समूहों की स्टॉल्स पर पहुंचकर महिलाओं को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए प्रदर्शित उत्पादों के बारे में महिलाओं से जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने जोधपुर के केरू गांव की हुनरमंद महिला श्रीमती गीता देवी के स्टॉल पर हाथों से बनाए बाजरे के बिस्किट का स्वाद लिया और तारीफ की। गीता देवी के अनुसार बिस्किट में देसी बाजरे के साथ तिल के उपयोग से बिस्किट स्वादिष्ट व पौष्टिक बन जाते हैं। मुख्यमंत्री ने बाजरे के बिस्किट खरीदे। मुख्यमंत्री ने समारोह में स्टॉल लगाने वाली महिलाओं के कार्यों, उनके आत्मविश्वास को सराहा और हौसला अफजाई की। श्रीमती गीता ने बताया कि लगभग 10 माह पूर्व राजीविका और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आरएसईटी) के द्वारा गांव की 12 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बाजरे के बिस्किट बनाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। मुख्यमंत्री ने महिला समानता दिवस पर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए 'महिला निधि' का लोकार्पण किया। इससे महिलाओं को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के अलावा व्यवसाय को बढ़ाने व उद्यमिता के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध हो सकेगा। महिलाओं

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
उप निदेशक (जनसंपर्क)

की स्थिति बेहतर बनाने और उनके साथ समानता के व्यवहार के लिए सामाजिक सोच में बदलाव की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार सहित स्वयं की सुरक्षा और आईटी प्रशिक्षण के लिए काम हो रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश के चहुंमुखी विकास में भागीदारी निभा सकें।

राज्य सरकार की अनेक योजनाएं महिला केन्द्रित हैं, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता का परिचायक हैं। राज्य के विकास तथा सुशासन में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है। पिछले तीन वर्षो में महिला और बालिकाओं के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा 52 योजनाएं बनाई गई हैं।

राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने, उन्हें आत्मरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने तथा अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में सजग करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में क्रांतिकारी सुधारों की वजह से महिलाएं पहले की तुलना में अधिक

सशक्त हुई हैं। उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है और वे निडरता से अपने काम-काज की बागडोर संभाल रही हैं।

महिला निधि से मिलेगा राज्य की महिलाओं को सम्बल

बजट 2022-23 में महिला निधि की स्थापना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के माध्यम से की गई है। तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है, जहां महिला निधि की स्थापना की गई है। महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैकों से ऋण दिलाने, गरीब, सम्पत्तिहीन और सीमान्त महिलाओं की आय बढ़ाने व कौशल विकास कर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि की स्थापना की गई है। इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपये तक के ऋण 48 घण्टे में व 40,000 रुपये से अधिक के ऋण 15 दिवस की समय सीमा में आवेदित सदस्यों के समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में 2 लाख 70 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें 30 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें लगभग 6 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। राज्य में कुल 36 लाख परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से राजस्थान महिला निधि से लाभ मिलेगा।

6 जिलों के 386 स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को 1 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि राजस्थान महिला निधि से ऋण के रूप में प्रदान की गई। सामुदायिक स्तर पर विशिष्ट कार्य करने के लिए राजीविका कम्यूनिटी कैडर की 8 महिलाओं को भी पुरस्कृत किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी

आमजन को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपये तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क ओपीडी, आईपीडी, निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध हो रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्च भी सरकार स्वयं वहन कर रही है।

शिक्षा क्षेत्र में लड़कियां आगे

शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी का सफल परिणाम है कि आज उच्च शिक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़कियां प्रवेश ले रही हैं। प्रदेश में राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू करके अभिनव प्रयोग किया गया है। यहां बच्चे प्राइमरी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं। राज्य सरकार का 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की योजना है, जिससे वे राजकीय योजनाओं के बारे में अद्यतन हो सकेगी और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे।

सामाजिक सुरक्षा: मुख्य ध्येय

हर प्रदेशवासी की सामाजिक सुरक्षा राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है, जिनमें विधवा, एकल नारी व बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं।

जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू कर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा सहित आधारभूत ढांचे का विस्तार और विकास किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह, आशा सहयोगिनी व सुरक्षा सखियों को राज्य सरकार की योजनाएं को घर-घर तक ले जाने का आह्वान किया गया है।

उड़ान योजना के द्वितीय चरण के लिए 600 करोड़ रुपये

उड़ान योजना के द्वितीय चरण में 1 करोड़ 45 लाख किशोरियों एवं महिलाओं के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के प्रथम चरण से 29 लाख किशोरियां और महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एमओयू

निजी कंपनियों के साथ उत्पादों के ऑनलाइन विक्रय के लिए एमओयू करार किया गया। इससे 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर सूचीबद्ध किया जाएगा और देश भर के लाखों ग्राहकों को उत्पाद उपलब्ध कराये जाएंगे। इसके द्वारा, कारीगरों और बुनकर समुदाय को सशक्त बनाने व उन्हें भी विक्रेता बनाकर डिजिटल समावेश हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में वर्क फ्रोम होम जॉब वर्क योजना व पोर्टल का भी शुभारम्भ किया गया है।

कॉकलियर इम्प्लांट

राजस्थान में निःशुल्क उपलब्ध

लीलाधर
सहायक निदेशक,जनसम्पर्क

कुमकुम ने अपने 7वें जन्मदिन पर अपने परिवार सहित मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। श्री गहलोत के निर्देश पर कुमकुम का पिछले साल मुख्यमंत्री राहत कोष से निःशुल्क कॉकलियर इम्प्लांट करवाया गया था। मुख्यमंत्री ने कुमकुम से मिलकर संतोष जताया कि वह अब ठीक से बोलने-सुनने के साथ ही स्कूल भी जाने लगी है। कुमकुम के माता-पिता ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से कॉकलियर इम्प्लांट जैसी महंगी प्रक्रिया राजस्थान में निःशुल्क उपलब्ध है।

कॉकलियर इम्प्लांट ने बदला सैकड़ों मूक-बधिर बच्चों का जीवन

प्रदेश में मुख्यमंत्री सहायता कोष से सैकड़ों मूक-बधिर बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी से जीवन बदल गया है। जो बच्चे जन्म से सुनने में सक्षम नहीं होते उनमें बोलने की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती है। गूंगेपन और बहरेपन के कारण बच्चे का जीवन खुशियों की चहकार से वीरान हो जाता है तथा सामान्य बच्चों के समान जीवन जीने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

क्या होता है कॉकलियर इम्पलांट

कॉकलियर इम्प्लांट एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो व्यक्ति को आवाज को महसूस करने में मदद करता है। यह उन लोगों के काम आता है जिनकी श्रवण क्षमता बहुत कम है या फिर जिनमें बहरेपन की समस्या पाई जाती है। इस डिवाइस में मुख्यरूप से दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा एक माइक्रोफोन होता है जो वातावरण से ध्वनि को प्राप्त करता है, यह कान के बाहरी हिस्से में पीछे की तरफ लगाया जाता है। इस डिवाइस के दूसरे हिस्से को सर्जरी की मदद से कान में अंदर लगाया जाता है जो इस ध्वनि को व्यक्ति को महसूस करवाने में मदद करता है। अक्सर लोग कॉकलियर इम्प्लांट और हियरिंग एड को एक ही समझते है। लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है। हियरिंग एड सिर्फ कानों तक आने वाली ध्वनि को एम्पलीफाई करता है, जिससे कम सुनने वाले व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देने लगती है। हियरिंग एड कान के डैमेज हिस्से का ही प्रयोग ध्वनि पहुंचाने के लिये करता है, जबकि कॉकलियर इम्प्लांट कान के डैमेज हिस्से का प्रयोग किये बिना सीधे दिमाग के ऑडिटरी नर्व तक ध्वनि के सिग्नल पहुंचा देता है और व्यक्ति में सुनने की क्षमता पैदा हो जाती है।

कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के पश्चात दो तीन वर्ष तक स्पीच थैरेपी करवायी जाने से बच्चे में बोलने की क्षमता विकसित हो जाती है तथा बच्चा बोलने एवं सुनने में सक्षम हो सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सकों की राय के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के परिणाम आशाजनक रहते है। यह सर्जरी फिलहाल काफी महंगी है और अल्प आय वर्ग के परिवार इसका खर्च वहन नहीं कर पाते है।

अल्प आय वर्ग के बच्चों के लिये कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपनी सहृदयता के लिए जाने जाते है। महात्मा गांधी के विचार और दर्शन पर चलने वाले मुख्यमंत्री ने बच्चों में बहरेपन की समस्या को समझा। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के मूक-बधिर बच्चों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए एक कल्याणकारी कदम उठाया है और अपने पूर्व कार्यकाल के दौरान दिसम्बर, 2010 में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से सवाई मानसिंह चिकित्सालय द्वारा निर्धारित दर पर शत-प्रतिशत सहायता करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इस समस्या की पहचान के लिये राज्य सरकार ने सम्भागीय स्तर के मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालयों में बच्चों की उत्सर्जन जांच की सुविधा उपलब्ध करवायी है।

कौन ले सकता है मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद

मूक-बधिर बच्चों की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 1 अप्रेल, 2022 से शामिल किया गया।

राजस्थान प्रदेश भर में उमड़ा खेल भावना का महाज्वार

खिलाड़ियों के महाकुंभ में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने उत्साह से लिया हिस्सा

छह खेलों की स्पर्धाओं ने लिया ग्राम्य उत्सव का स्वरूप

डॉ. दीपक आचार्य
उप निदेशक, जनसम्पर्क

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान प्रदेश भर में खेलों का माहौल बनाने तथा विभिन्न खेलों की ग्राम्य प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तराशने के महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य को लेकर आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 की प्रदेश भर में हर स्तर पर सराहना हुई है।

इससे राज्य में खेलों का व्यापक माहौल बनने के साथ ही खिलाड़ियों में अपार उत्साह का संचार हुआ है। ग्रामीण खेलों की खास बात यह रही है कि इसने आयु के बंधन को दरकिनार कर हर आयु वर्ग के ग्रामीण खिलाड़ियों को अवसर प्रदान किया और नई जीवनशक्ति का संचार किया।

राजस्थान में खेलों के महाकुंभ के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस पर पहली बार आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 का राज्यस्तरीय शुभारंभ जोधपुर में हुआ।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले की लूणी पंचायत समिति अन्तर्गत पाल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु मेला मैदान पर आयोजित भव्य राज्यस्तरीय समारोह में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने खेल ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी लेकर वहां से ग्रामीण खेलों का शुभारम्भ किया। इस दौरान राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल-2022 की मशाल मुख्यमंत्री द्वारा खिलाड़ियों को सौंपी गई।

शहरी क्षेत्रों में भी ओलंपिक खेल, ग्रामीण ओलंपिक हर साल होंगे

ग्रामीण ओलंपिक की ही तर्ज पर नगर निकायों की सहभागिता तय करते हुए शहरी क्षेत्रों में भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। खेलों के प्रति ग्रामीणों की रुचि बनाए रखने के लिए ग्रामीण ओलंपिक खेलों को हर वर्ष आयोजित करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। अब ग्रामीण ओलंपिक भी हर साल होंगे ताकि लोगों में खेल भावना एवं अभ्यास का दौर निरन्तर बना रहे।

राजस्थान के लिए ऐतिहासिक एवं अपूर्व आयोजन

राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के प्रदेशव्यापी आयोजन अभूतपूर्व है। यह दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक है। खेलों के इस महाकुंभ में हर आयु और वर्ग का व्यक्ति अपनी खेल प्रतिभा से रूबरू करा रहा है।

निखरेंगी खेल प्रतिभाएं

'खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान' का प्रदेश का लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। यहां न कोई हार है, न कोई जीत। राजस्थान का यह अनूठा प्रयोग कामयाबी का इतिहास रचेगा और इसके माध्यम से प्रदेश से वैश्विक स्तर की खेल प्रतिभाएं निखरकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को तलाशकर उन्हें प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना ही हमारा उद्देश्य है। खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य व व्यक्तित्व के साथ ही मानवीय गुणों का भी विकास होता है जिससे सामाजिक विकास और कल्याण को नई दिशा प्राप्त होती है।

सद्भावना और सामूहिक विकास की सोच को सम्बल मिलेगा

इन खेलों से उभरने वाली प्रतिभाएं आगे चलकर ओलंपिक और कॉमनवैल्थ में बेहतर प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। इन खेलों से खेल भावनाओं का विकास होगा, जिससे आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना और पारस्परिक विकास की सौहार्दपूर्ण सोच विकसित होगी। इन खेलों का उद्देश्य समाज और क्षेत्र में खेल भावना का संचार करना है।

इन खेलों में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लगभग 30 लाख खिलाड़ी छह खेलों के लिए पंजीकृत हुए हैं। खिलाड़ियों की 2 लाख 21 हजार 55 टीमें बनी हैं जिनमें 20 लाख 37 हजार पुरुष तथा 10 लाख महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं।

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द के नाम पर हर ब्लॉक पर स्टेडियम बनाने का बड़ा निर्णय किया है। जोधपुर जिले में 295 ग्राम पंचायतों में 30 से 50 लाख रुपये तक की धनराशि के खेल मैदान मनरेगा में स्वीकृत किए गए हैं। इस काम के लिए 11 करोड़ रुपये का जन सहयोग जुटाने के लिए सरपंचों की प्रशंसा की।

वर्ल्ड रिकार्ड का प्रमाण पत्र सौंपा

पाल ग्राम पंचायत में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में प्रदेश में

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक-2022 में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की अधिकतम भागीदारी के लिए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज होने पर इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया।

गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में खेलों की अलख जगाने व ग्रामीणों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, भाईचारे, आपसी प्रेम, सद्भावना एवं सहयोग का माहौल तैयार करने के उद्देश्य से 29 अगस्त को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज किया गया है।

- यह संभवतः दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है।
- 5 अक्टूबर तक 6 खेलों का होगा आयोजन
- 29 लाख 80 हजार से अधिक खिलाड़ी मैदान में
- पुरुष खिलाड़ी 20 लाख 37 हजार 564
- महिला खिलाड़ी 9 लाख 41 हजार 671
- 2 लाख 21 हजार 55 टीमें के बीच होंगे मुकाबले
- प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के खेल मैदानों में आयोजन
- जिला प्रभारी मंत्री जिलों के आयोजनों में हुए शामिल। समारोह का उद्घाटन कर खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित।

6 खेलों का आयोजन

कबड्डी	शूटिंगबॉल	वॉलीबॉल
हॉकी	खो-खो	टेनिस बॉल क्रिकेट

इस तरह हो रहा है प्रतियोगिताओं का आयोजन
ग्राम पंचायत स्तरीय खेल - 29 अगस्त से 1 सितंबर तक
ब्लॉक स्तरीय खेल- 12 सितंबर से 15 सितंबर तक
जिला स्तरीय खेल- 22 सितंबर से 25 सितंबर तक
राज्य स्तरीय खेल- 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक
आयु वर्ग - खिलाड़ी (कुल - 29 लाख 80 हजार से अधिक)
10 से 20- 20,93,911
20 से 30- 5,16,351
30 से 40- 1,27,973
40 से 50- 40,482
50 से 60- 15,119
60 से 70- 4,443
70 प्लस- 1,567

खेल और कुल खिलाड़ी
कबड्डी: 11 लाख 86 हजार 93
पुरुष- 9 लाख 35 हजार 335
महिला- 2 लाख 50 हजार 758
टेनिस बॉल क्रिकेट: 7 लाख 4 हजार 788
पुरुष- 6 लाख 63 हजार 830
महिला- 40 हजार 958
वॉलीबॉल: 3 लाख 4 हजार 892
पुरुष- 2 लाख 41 हजार 794
महिला- 63 हजार 98
हॉकी: 1 लाख 31 हजार 87
पुरुष- 92 हजार 582
महिला- 38 हजार 505
शूटिंग बॉल: 1 लाख 4 हजार 19
पुरुष- 1 लाख 4 हजार 019
खो-खो: 5 लाख 48 हजार 356
महिला- 5 लाख 48 हजार 352

ग्राम पंचायत स्तर पर कुल टीमें - 2 लाख 21 हजार 055
कबड्डी में- 91,891 टीमें
टेनिस क्रिकेट- 46,297 टीमें
वॉलीबॉल- 29,730 टीमें
हॉकी- 5,796 टीमें
शूटिंग वॉलीबॉल- 8,513 टीमें
खो-खो- 38,825 टीमें

इन जिलों में 1 लाख से अधिक खिलाड़ी
भीलवाड़ा- 2 लाख 25 हजार 578
नागौर- 2 लाख 25 हजार 565
उदयपुर- 2 लाख 3 हजार 817
अलवर- 1 लाख 83 हजार 583
श्रीगंगानगर- 1 लाख 45 हजार 635
हनुमानगढ़- 1 लाख 45 हजार 185
बीकानेर- 1 लाख 14 हजार 324
झुंझुनूं- 1 लाख 13 हजार 605
बूंदी- 1 लाख 10 हजार 453
सीकर- 1 लाख 2 हजार 474
बाड़मेर- 1 लाख 1 हजार 232

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का मेले की तरह माहौल है। इनमें उम्र की कोई सीमा नहीं है एवं सभी आयु वर्गों के लोग उत्साहित होकर मैदान में उतर रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए राजस्थान सरकार ने 40 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। इनके आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर इन्हें आगे लाना एवं प्रोत्साहित करना है। इन खेलों से गांवों में आपसी खेल भावना के जरिए सद्भाव बढ़ेगा। इन खेलों के आयोजन के लिए पंचायत स्तर पर खेल मैदान तैयार करवाए जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार ने मैडल जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बड़ी वृद्धि की है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरी दी गई है। प्रशिक्षकों के लिए भी पेंशन स्कीम लागू की गई है। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

जसदेव सिंह

आवाज ही जिनकी पहचान थी

डॉ. कल्याण प्रसाद वर्मा
लेखक

'अरे आपने तो दिल की धड़कनें ही बढ़ा दी थी। आप इतना फास्ट कैसे बोल लेते हैं?' ये शब्द थे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के। यह शब्द जसदेव सिंह के लिए कहे गए थे। वे हिन्दी कमेंट्री के पर्याय थे, आवाज ही उनकी पहचान थी। भारत की आवाज आदि विशेषणों से वे पहचाने जाते थे। नि:संदेह आवाज की दुनिया रेडियो जैसे संचार माध्यम से अपनी वाणी को मुखर करने वाले जसदेव सिंह न केवल शब्दों के खिलाड़ी, प्रखर वक्ता बल्कि लेखनी के धनी ख्यात साहित्यकार, उद्घोषक व सत्यान्वेषी पत्रकार भी रहे। ऐसी शख्सियत का जन्म राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बौंली गांव में 18 मई 1931 को हुआ और निधन 87 वर्ष की आयु में 25 सितम्बर 2018 को जयपुर में हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्मम हत्या से शोकमग्न था, जाने-माने समाचार वाचक और कमेंटेटर स्व. मेलविन डिमेलो से अंग्रेजी में गांधी की अंतिम यात्रा का आंखों देखा हाल सुना तो उनका दिल बैठ गया। यों उद्घोषक बनने का जुनूनी गुण जसदेव सिंह में छात्र-जीवन से ही घर किये हुए था, यही कारण था कि वे जयपुर में होने वाले जयपुर ओलम्पिक के खेलों का प्रसारण कनस्तर से बने भोंपू से करते थे, जो बाद में वे एक प्रसिद्ध उद्घोषक के रूप में स्थापित हुए।

पहली बार माइक्रोफोन का सामना वर्ष 1949 में सेवानिवृत्त सैनिकों की रैली में मुख्य अतिथि के रूप में आए सेनापति जनरल के.एम. करिअप्पा की सभा के प्रसारण में उन्होंने बोलना शुरू किया और सेवापर्यंत जारी रहे। दुनिया के वे पहले उद्घोषक थे जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अधिवेशन में 16 सितम्बर 1988 को 'ओलंपिक ऑर्डर' से नवाजा गया।

वर्ष 1964 के अक्टूबर में हुए टोकियो आलंपिक खेलों को 'कवर' करने के लिए चुना गया, उससे अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की कवरेज के प्रति उनका आकाशवाणी में विश्वास भी दृढ़ से दृढ़तर होता चला गया। वर्ष 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम 'संकल्प' जो सैनिक अस्पतालों में मोर्चे से ज़ख्मी होकर लौटे योद्धाओं की बहादुरी पर आधारित होता था, बहुत ही उत्साहवर्द्धक और उत्प्रेरक तो होता ही था साथ ही जानकारियों के हिसाब से भी 'गागर में सागर' के समान था। इस पहल की बहुत सराहना हुई तथा यह विश्वास भी दृढ़ हुआ कि रेडियो और टीवी कार्यक्रमों में आम नागरिकों की सहभागिता ही इन माध्यमों को 'देश की आवाज' का दर्जा दे सकती है। वर्ष 1975 में कुआलालम्पुर में तीसरे विश्वकप हॉकी के फाइनल मैच की कमेंट्री भी हिंदी में की थी।

आवाज की दुनिया के ऐसे विरले खेल पत्रकार रहे जिनका शब्दों पर ऐसा अधिकार था कि आंखों के आगे दृश्य चित्रण स्वत: ही दृश्यमान होता चलता था। इतना ही नहीं उनके द्वारा की गयी कमेंट्रियों का यह वैशिष्ट्य ही था कि वे अवसर के अनुकूल श्रव्य माध्यम के लिए वातावरण, घटना या स्थान विशेष को अपनी वाणी से फिल्माते हुए चलते जिससे घटना आगे से आगे आंखों के सामने उभरती-चलती-दिखती थी। जसदेव सिंह ने सभी खेलों पर समान अधिकार के साथ ओलंपिक, एशियन गेम्स व हॉकी वर्ल्ड कप तक कवर किए थे। कोलकाता में मैच के दौरान खेल की ऐसी कमेंट्री की थी कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे।

देश की भाषा हिंदी में खेलों की हृदयस्पर्शी कमेंट्री करके उन्होंने खेलों को किसानों से लेकर गृहणियों तक पहुंचा दिया। हॉकी और क्रिकेट जैसे खेलों को लोकप्रिय बनाने में उनका बड़ा हाथ रहा ... हिन्दी-उर्दू के मिश्रण से बनी उनकी बोली दिल से निकलती और सीधे दिल में असर करती थी। हिन्दी भाषा को उसका उचित स्थान दिलाने में जसदेव सिंह की कोशिशें भी काफी कारगर साबित हुईं। जब-जब भारत में हिंदी कमेंट्री की बात होगी तब-तब जसदेव सिंह को याद किया जाएगा। उनका यह समवेत रूप आवाज की दुनिया में उनकी शिखर-पुरुष की छवि का आइना ही माना जाएगा। रेडियो जैसे माध्यम की शक्ति को आमजन में जसदेव सिंह ने बीसवीं सदी के चौथे-पांचवे दशक में ही पहचान दिला दी थी।

कुम्भलगढ़ किला

वीरता, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक कुम्भलगढ़ किला समुद्रतल से 3568 फीट की ऊँचाई पर राजसमंद जिले के सादड़ी गांव के पास अरावली पर्वतमाला के उत्तुंग शिखर पर स्थित है। इस किले में भारत की पहली सबसे लम्बी एवं विश्व में दूसरे नंबर की लम्बी सुरक्षा दीवार है। यह किला विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित हैं, जो अजयगढ़ नाम से भी विख्यात है।

आलेख एवं छाया : गोपाल गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार

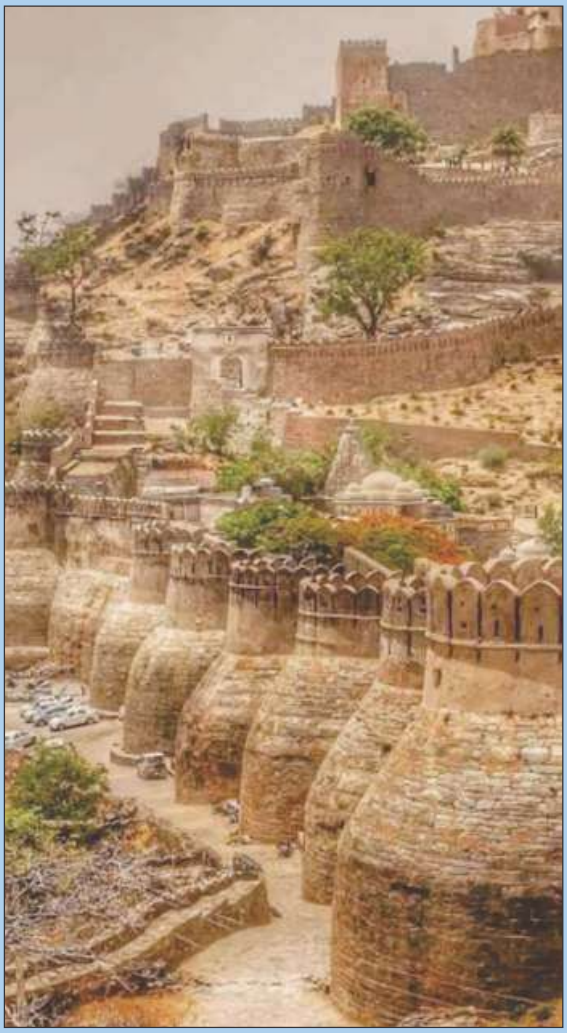

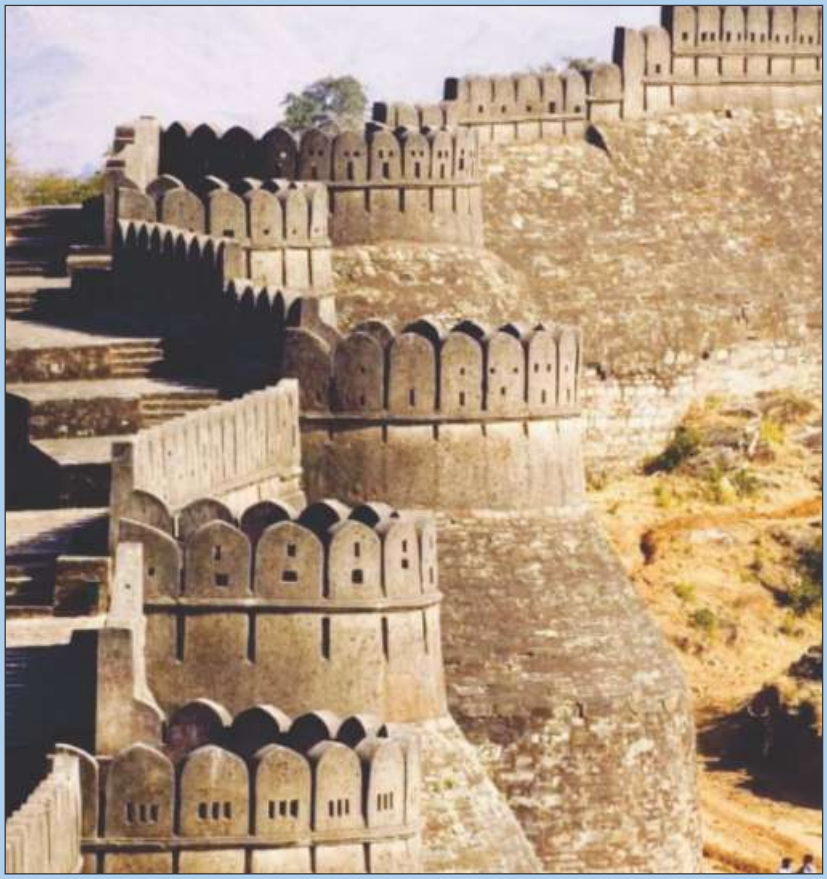

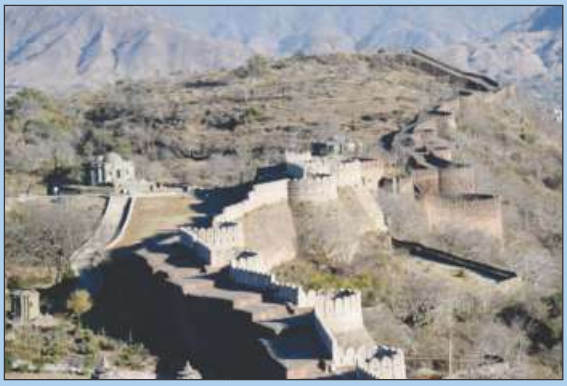

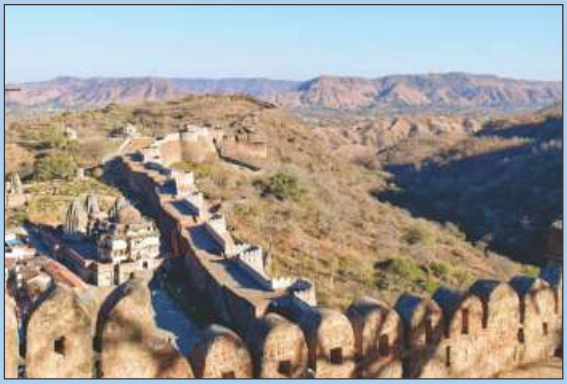

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

तस्वीर बदलाव की

तब

अब

राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी
https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक – सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक – श्रीमती अलका सक्सेना, मै. कृष्णा प्रिन्टर्स, डी–14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 30.56 रुपये ● 5,00,000 प्रतियां